

मंत्रालयों और विभागों की वर्षांत समीक्षा

भाग-2 (पूरक डॉक्यूमेंट: 2024)



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



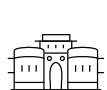
जोधपुर



लखनऊ



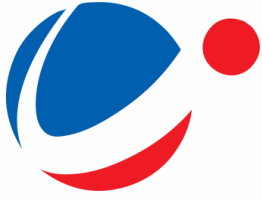
प्रयागराज



पुणे



राँची



VISION IAS

www.visionias.in

मंत्रालयों और विभागों की वर्षात समीक्षा

(भाग-2)

(पूरक डॉक्यूमेंट)

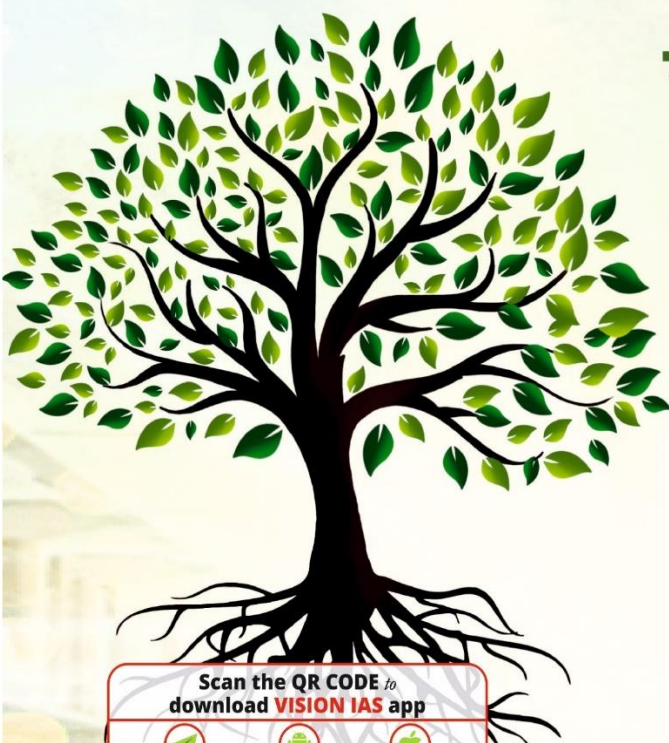
विषय सूची

1. वित्त मंत्रालय	3
1.1. आर्थिक कार्य विभाग	3
1.2. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	3
1.3. लोक उद्यम विभाग	4
1.4. व्यय विभाग	4
1.5. वित्तीय सेवाएं विभाग	5
1.6. राजस्व विभाग	5
2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	7
2.1. वाणिज्य विभाग	7
2.2. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग	10
3. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	14
4. रेल मंत्रालय	16
5. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	18
6. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	20
7. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	21
7.1. पशुपालन और डेयरी विभाग	21
8. ग्रामीण विकास मंत्रालय	22
8.1. ग्रामीण विकास विभाग	22
8.2. भूमि संसाधन विभाग	23
9. श्रम और रोजगार मंत्रालय	24
10. शिक्षा मंत्रालय	25
10.1. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	26
11. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	29
12. परमाणु ऊर्जा विभाग	31
13. संचार मंत्रालय	31
13.1. डाक विभाग	32
13.2. दूरसंचार विभाग	32
14. विधि और न्याय मंत्रालय	34
15. विद्युत मंत्रालय	36

16. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	36
17. खान मंत्रालय	37
18. आयुष मंत्रालय	40
19. भारी उद्योग मंत्रालय	40
20. जनजातीय कार्य मंत्रालय	41
21. संस्कृति मंत्रालय	43
22. संसदीय कार्य मंत्रालय	44
23. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	44
24. वस्त्र मंत्रालय	45
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	47
26. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	47
27. नागरिक उड्डयन मंत्रालय	49

नोट: इस डॉक्यूमेंट में वर्ष 2024 के संदर्भ में प्रेस सूचना ब्यूरो पर प्रकाशित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षा का संक्षिप्त व्योरा प्रदान किया गया है। इसमें विभिन्न सरकारी क्षेत्रों की पहलों, प्रगति और उपलब्धियों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट से UPSC के आगामी इंटरव्यू की तैयारी के लिए तेजी से रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही, इसका उपयोग करके अभ्यर्थी अपने नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं।

भाग-2 इसमें भारत सरकार के 27 मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षाएं शामिल हैं, जैसा कि विषय-सूची में भी दिया गया है। भारत सरकार के 20 मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षा का संक्षिप्त व्योरा भाग-1 में प्रदान किया गया है।



फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI : 4 फरवरी, 11 AM

JAIPUR: 20 जनवरी

JODHPUR: 3 दिसंबर

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW

1. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance)

1.1. आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs)

सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर फ्रेमवर्क 2024-27	- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्क देशों के बीच मुद्रा विनिमय व्यवस्था और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ाने के लिए नए फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। - भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए 2 बिलियन डॉलर के मौजूदा डॉलर/यूरो स्वैप विंडो के अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये की एक अलग भारतीय रुपया स्वैप विंडो की शुरुआत की गई।
भारत-UAE द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)	- भारत-संयुक्त अरब अमीरात BIT 13 फरवरी, 2024 को हस्ताक्षरित और 31 अगस्त, 2024 से प्रभावी हुई है। यह लागू होने के बाद से निवेश के लिए न्यूनतम मानक उपाय और राष्ट्रीय उपाय सुनिश्चित करके निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएगा। - इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं: निवेश की एक क्लोज्ड परिसंपत्ति-आधारित परिभाषा, पूर्ण न्याय के प्रावधान और निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र। इस तंत्र में तीन साल के भीतर स्थानीय विवाद समाधान का विकल्प दिया गया है।
भारत-उज्बेकिस्तान BIT	- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निवेशकों को पारस्परिक रूप से उचित संरक्षण प्रदान करना। - पूर्ण न्याय भेदभाव-रहित न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना। - विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच प्रदान करना। - निवेशों को अधिग्रहण से सुरक्षा प्रदान करना, पारदर्शिता, हस्तांतरण और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) सुधार	- DEA ने राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों में बुनियादी ढांचे के विकास का मूल्यांकन और उसे प्रोत्साहित करके सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना तत्परता सूचकांक (National Infrastructure Readiness Index: NIRI) लॉन्च किया है। - इसके अतिरिक्त, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सीमा-पार निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेश नियमों में संशोधन किए गए हैं, जिनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विनियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम शामिल हैं।

1.2. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग {Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM)}

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (CPSEs)	- सरकार CPSEs के संबंध में एक समग्र लोक परिसंपत्ति प्रबंधन रणनीति का अनुसरण कर रही है, जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन में वृद्धि करना, लगातार लाभान्ध देने को प्रोत्साहित करना, और मूल्य वृद्धि तथा विकास सुनिश्चित करना है। - इसमें प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और एक सुनियोजित विनिवेश रणनीति शामिल है, जिसमें स्टॉक मार्केट में CPSE सूचकांकों ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया है।
ऑफर फॉर सेल (OFS)	- चालू वित्त वर्ष के दौरान, DIPAM ने भारतीय साधारण बीमा निगम (GIC) के 'ऑफर फॉर सेल' की पेशकश की है। - OFS के ओवर सब्सक्रिप्शन होने के कारण ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग किया गया। - DIPAM ने HAL, कोल इंडिया लिमिटेड, RVNL, SJVN लिमिटेड और HUDCO जैसे CPSEs के लिए मूल्य सृजन हेतु ऑफर फॉर सेल (OFS) मार्ग का भी उपयोग किया, जिसके तहत OFS से सामूहिक रूप से 13,728 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स (IPOs)	DIPAM ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (IREDA/ इरेडा) और MSTC लिमिटेड सहित कई प्रमुख संस्थाओं के IPOs को सफलतापूर्वक लॉन्च किया।

1.3. लोक उद्यम विभाग {Department of Public Enterprises (DPE)}

पूँजीगत व्यय (CAPEX) में वृद्धि	- लोक उद्यम विभाग ने गत वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। - पूँजीगत व्यय संबंधी उपलब्धियां क्रमशः वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानों के 100 प्रतिशत और 108 प्रतिशत से अधिक थी।
CPSEs की मान्यता	- असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हुए, लोक उद्यम विभाग (DPE) ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को महारत्न का दर्जा दिया। - DPE ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, NHPC और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सहित कई 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों' को नवरत्न का दर्जा दिया। - ये मान्यताएं CPSEs को महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू करने, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करती हैं।
नीतिगत सुधार	- सितंबर 2024 में जारी संशोधित दिशा-निर्देशों ने महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न CPSEs के बोर्डों द्वारा संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बना दिया। - इसी तरह, मई 2024 में जारी किए गए नए निर्देशों ने मौजूदा CPSEs के वर्गीकरण के लिए प्रक्रिया को सरल बना दिया। - DIPAM ने CPSEs के पूंजी पुनर्गठन पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए: CPSE के मूल्य और शेयरधारकों के लिए कुल रिटर्न को बढ़ाने के लिए।

1.4. व्यय विभाग (Department of Expenditure)

लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)	- DoE ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,206 से अधिक योजनाओं के लिए वास्तविक समय, पारदर्शी फंड ट्रांसफर को सक्षम करके, 2.23 लाख करोड़ रुपये के लेनदेन को प्रोसेस करके डिजिटल इंडिया मिशन का समर्थन किया है। 117 बाहरी प्रणालियों के साथ इसके व्यापक एकीकरण और प्रमुख बैंकों के साथ निर्बाध इंटरफेस ने दक्षता और जवाबदेही को बढ़ाया है।
राज्य के वित्त को मजबूत करना	15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, DoE ने अतिरिक्त उधार क्षमता, प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन और आपदा से उबरने, स्वास्थ्य देखभाल और क्षेत्रीय विकास के लिए अनुदान की सुविधा देकर राज्य के वित्त को मजबूत किया है। - वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, निवल उधार सीमा 9.40 लाख करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी, जिसमें बिजली क्षेत्र के सुधारों के लिए GSDP (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) का 0.5% अतिरिक्त आवंटित किया गया था।
सार्वजनिक खरीद व्यवस्था में सुधार	सामान्य वित्तीय नियमों (GFRs) के तहत बढ़ी हुई वित्तीय सीमा और 2024 में संशोधित खरीद मैनुअल जारी होने के साथ, सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में सुधार प्रमुख फोकस बना हुआ है।
वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 2024	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 2024, विभागों और व्यक्तियों को सशक्त बनाकर निर्णय लेने को और सरल बनाता है, वित्तीय प्रबंधन में दक्षता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है।
एकीकृत पेंशन योजना (UPS)	एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुधार भी पेश किए हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए सुनिश्चित पेंशन और मुद्रास्फीति-समायोजित लाभों की गारंटी देती है। 1 अप्रैल, 2025 से कार्यान्वयन के लिए निर्धारित यह योजना अपने कार्यबल का कल्याण सुरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
आपदा प्रबंधन पहल	आपदा प्रबंधन पहल में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को समय पर फंड जारी करने के साथ-साथ अग्निशामक और आपातकालीन सेवाओं का आधुनिकीकरण भी शामिल है।

1.5. वित्तीय सेवाएं विभाग {Department of Financial Services (DFS)}

बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है: संपत्ति की गुणवत्ता: सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs) मार्च 2018 के 10.36 लाख करोड़ (11.18%) रुपये से घटकर मार्च 2024 में 4.75 लाख करोड़ (2.67%) रुपये हो गई है। रेजिलिएंस: प्रॉविजनिंग कवरेज अनुपात (PCR) मार्च 2015 में 49.31 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 92.52 प्रतिशत हो गया। पूंजी उपलब्धता: पूंजी से जोखिम (भारित) संपत्ति अनुपात (CRAR) सुधरकर जून 2024 में 14.79 प्रतिशत पर पहुंच गया, जो मार्च 2015 में 12.94% था। लाभप्रदता: SCBs ने वित्त वर्ष 2022-23 में 2.63 लाख करोड़ रुपये के निवल लाभ के मुकाबले 3.50 लाख करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक कुल निवल लाभ दर्ज किया है।
डिजिटल भुगतान में वृद्धि	- डिजीधन मिशन के तहत जनवरी से नवंबर 2024 तक डिजिटल भुगतान लेनदेन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और यह 223 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। - BHIM-UPI के माध्यम से 15,547 करोड़ से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए, जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है।
वित्तीय समावेशन योजनाएं	- DFS ने निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से वित्तीय समावेशन को प्राथमिकता देना जारी रखा: - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - मुद्रा - स्टैंड अप इंडिया - अटल पेंशन योजना - उपर्युक्त कार्यक्रमों ने लाखों लोगों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए, आवश्यक बैंकिंग, बीमा और पेंशन सेवाओं तक पहुंच का विस्तार किया है।
कृषि ऋण विस्तार	- कृषि ऋण वितरण वित्त वर्ष 2014-15 में 8.45 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 24.30 लाख करोड़ रुपये हो गया। - किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना महत्वपूर्ण है, ये 7.92 करोड़ से अधिक सक्रिय KCC खाता धारक किसानों को समय पर ऋण सहायता प्रदान करती है।

1.6. राजस्व विभाग (Department of Revenue)

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की पहल	CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने सक्रिय हेल्पडेस्क और फेसलेस प्रक्रियाओं के माध्यम से करदाताओं को सहायता प्रदान की, जिससे पारदर्शिता और दक्षता को प्रोत्साहन मिला। TIN 2.0, जैसे नवाचारों ने ITRs की प्री-फिलिंग और अपडेटेड रिटर्न प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बना दिया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) सुधार	वस्तु और सेवा कर (GST) में सुधार: - CBIC ने उन्नत डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके GST पंजीकरण प्रक्रियाओं को मजबूत किया, - उदाहरण के लिए, व्यवसायिक स्थलों की जियो-टैगिंग, और नॉन-फाइलर्स के लिए सिस्टम-आधारित पंजीकरण निलंबन। GSTR-1 और GSTR-3B की क्रमिक फाइलिंग के अनुपालन को सरल बनाया गया, जिससे समय पर रिटर्न दाखिल करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हुई।

	- सीमा शुल्क का आधुनिकीकरण: - CBIC ने सीमा शुल्क दरों को युक्तिसंगत बनाने और कुछ मामलों को अपराध की श्रेणी से हटाने की दिशा में कदम उठाने जैसे सुधार किए। - ICEGATE 2.0 और एनोनीमाईज्ड एस्केलेशन मैकेनिज्म जैसी तकनीकी प्रगति ने कर प्रशासन का आधुनिकीकरण किया। - ढांचागत उन्नयन, जैसे प्री-गेट प्रसंस्करण सुविधाएं और नियंत्रण प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण ने परिचालन दक्षता में वृद्धि की।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) की उपलब्धियां	FATF मान्यता: वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) ने भारत के उच्च स्तर के तकनीकी अनुपालन और अवैध वित्त से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदमों को मान्यता देते हुए भारत को अपनी उच्चतम श्रेणी, "रेगुलर फॉलो अप" में रखा है। यह दर्जा G-20 के केवल चार देशों को प्राप्त है।



“You are as strong as your Foundation”

FOUNDATION COURSE

GENERAL STUDIES

PRELIMS CUM MAINS

2026, 2027 & 2028

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- ▶ Includes Pre Foundation Classes
- ▶ Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- ▶ Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- ▶ Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download **VISION IAS** app





DELHI: 21 JAN, 1 PM | 31 JAN, 5 PM
GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 6 JAN, 8 AM
हिन्दी माध्यम DELHI: 4 फरवरी, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN **BENGALURU: 18 FEB** **BHOPAL: 5 DEC** **HYDERABAD: 12 FEB** **JAIPUR: 20 JAN**
JODHPUR: 3 DEC **LUCKNOW: 11 FEB** **PUNE: 20 JAN** **ADMISSION OPEN** **CHANDIGARH**

2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce & Industry)

2.1. वाणिज्य विभाग (Department of Commerce)

विषय	प्रमुख पहल/ उपलब्धियां/ उपाय
मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ता	• भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA)- TEPA ○ हस्ताक्षरित समझौता: भारत ने 2024 में EFTA देशों (स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नार्वे और लिक्टेनस्टीन) के साथ व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) पर हस्ताक्षर किए। ○ प्रमुख विशेषताएं: ▪ अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ▪ भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता। ▪ "मेक इन इंडिया" और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। • भारत-यूरोपीय संघ (EU) FTA ○ प्रगति: सितंबर 2024 तक नौ दौर की वार्ता हो चुकी है। ○ दायरा: 2021 की लीडर्स पोर्टो घोषणा के बाद से वार्ता जारी, 23 नीतिगत क्षेत्रों/ अध्याय को कवर करता है। • भारत-UK FTA वार्ता ○ वर्तमान स्थिति: UK चुनाव के कारण मई 2024 में बातचीत रोक दी गई थी; G-20 शिखर सम्मेलन में UK के पीएम के साथ पीएम मोदी की मुलाकात के बाद 2025 की शुरुआत में इसे दोबारा शुरू करने की घोषणा की गई। • भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) ○ विकास: भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता (ECTA) की ओर से रखी गई नींव पर आधारित है। ECTA 29 दिसंबर, 2022 को लागू हुआ। ○ मुख्य विषय-वस्तु: वस्तुओं, सेवाओं में व्यापार, डिजिटल व्यापार और अन्य क्षेत्रों में व्यापार ○ प्रगति: अब तक कुल 10 औपचारिक दौर आयोजित किए जा चुके हैं। • भारत-श्रीलंका ETCA ○ उपलब्धि: जुलाई 2024 में संपन्न 14वें दौर की वार्ता के साथ बातचीत जारी है। ○ फोकस: सेवाओं, रूल्स ऑफ ओरिजिन और कपड़ों से संबंधित विशिष्ट व्यापार लाइनों। • भारत-आसियान ○ संबंध: 21वीं आसियान-भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक सितंबर 2024 में आयोजित की गई थी। ○ AITIGA समीक्षा: वर्ष 2024 के दौरान, AITIGA वार्ता के चार दौर आयोजित किये गये। समीक्षा 2025 में समाप्त करने का लक्ष्य है।
FTAs के जरिए सेवा व्यापार को बेहतर करना	विश्व व्यापार संगठन (WTO) • 13वीं मंत्रिस्तरीय कॉन्फ्रेंस (MC13) के परिणाम: ○ कृषि, सतत विकास और मात्स्यिकी में भारत के हितों की रक्षा की गई। ○ ई-ट्रांसमिशन के लिए सीमा शुल्क पर रोक MC14 (2026) तक बढ़ा दी गई है। ○ कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते को WTO में शामिल करने का समर्थन किया गया। • भारत का पक्ष ○ SPS समझौता: अधिकतम अवशेष सीमा (Maximum Residue Limits), क्षेत्रीय अनुकूलन और पारदर्शिता पर प्रस्ताव। ○ मात्स्यिकी हेतु सब्सिडी: छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले मछुआरों को नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिक समय देने और स्थायी विकास पर बल देने की वकालत की गई। ○ पर्यावरण प्रौद्योगिकी: जलवायु-लचीली प्रौद्योगिकियों पर मंत्रिस्तरीय घोषणा के लिए एक रोडमैप प्रस्तावित किया गया।

इंडो-पैसिफिक इकनोमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF)	• IPEF के चार स्तंभ हैं: ○ स्तंभ-I-व्यापार, ○ स्तंभ II : आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन ▪ नवंबर 2023 में, भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो फरवरी, 2024 में लागू हुआ। ▪ भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद (SCC) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ▪ स्तंभ II के तहत फार्मा/ हेल्थकेयर एक्शन प्लान टीम और शहरी ई-अपशिष्ट खनन कार्यक्रमों का नेतृत्व करना। ○ स्तंभ III: स्वच्छ अर्थव्यवस्था (क्लीन इकोनॉमी) ▪ समझौते पर सितंबर, 2024 को प्रधान मंत्री की USA यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते अक्टूबर, 2024 से लागू हैं। ▪ सिंगापुर में आयोजित स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक मंच के उद्घाटन समारोह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। ○ स्तंभ IV: निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (फेयर इकोनॉमी)
प्रमुख द्विपक्षीय सहयोग	• भारत-USA संबंध ○ अक्टूबर 2024 में 'क्रिटिकल मिनेरल सप्लाय चेन' समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए गए। ○ खनिज क्षेत्र में लचीलापन और मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम (IRA) के तहत प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाने का लक्ष्य। • भारत- UAE ○ 2030 तक गैर-तेल व्यापार में 100 मिलियन डॉलर का लक्ष्य। • भारत-मिस्र ○ फार्मास्यूटिकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन और स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में अवसरों की पहचान की गई। • भारत-अफ्रीका साझेदारी ○ 19वें CII भारत-अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के माध्यम से संबंधों को मजबूत किया गया। ○ डिजिटल परिवर्तन, पारंपरिक चिकित्सा और कच्चे हीरे की खोज में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया। • भारत-दक्षिण कोरिया: ○ जुलाई 2024 में नवीनतम दौर के साथ, भारत-दक्षिण कोरिया CEPA को अपग्रेड करने के लिए बातचीत चल रही है।
नई पहलें	• InCENT लैब-ग्रोन डायमंड परियोजना ○ IIT-मद्रास हीरा के आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए लैब-ग्रोन डायमंड के स्वदेशी उत्पादन के लिए अनुसंधान एवं विकास का नेतृत्व कर रहा है। • दुबई में भारत मार्ट ○ ट्रेड हब 2026 की पहली तिमाही में वाणिज्यिक संचालन शुरू करेगा। इसमें परिधान, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। • प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना (PMCSPIY) ○ असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में 10 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ • ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र ○ MSMEs की वैश्विक आउटरीच का समर्थन करने के लिए NCR क्षेत्र, बेंगलुरु और मुंबई के लिए पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
डिजिटल बदलाव	• ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म ○ सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया, यह 6 लाख से अधिक निर्यातकों को व्यापार-संबंधित संस्थाओं से जोड़ता है। • ऑनलाइन जनसुनवाई सुविधा ○ निर्यातकों के लिए त्वरित संपर्क मंच, पारदर्शिता और दक्षता में वृद्धि।

	• ई-BRC प्रणाली ○ बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट प्रणाली को डिजिटल बनाकर प्रति वर्ष 125 करोड़ रुपये की बचत। • व्यापार सुविधा मोबाइल ऐप ○ नीतियों और आवेदन की स्थितियों पर रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है।
बागवानी बोर्ड	• कॉफी निर्यात: 1047 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 46% अधिक है। • चाय का निर्यात: 525.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो 13.43% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। • मसाला निर्यात: मूल्य में 10.40% की बढ़ोतरी के साथ, यह 2476.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। अकेले अक्टूबर 2024 में मसालों का निर्यात 30.91% बढ़ा। • इनरोड (INROAD) परियोजना: 1,25,722.47 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य पूरा हो चुका है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1,40,000 से अधिक लघु उत्पादकों को लाभ मिला है। • नवाचार और सहयोग: ○ उच्च उपज देने वाली इलायची की किस्म 'ICRI 10' पेश की गई। ○ सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता ज्ञापन। • व्यापार भागीदारी: ○ Gulfood 2024 (कॉफी), BATIC 2024 (चाय), और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 जैसे वैश्विक कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)	• निर्यात संवर्धन पूंजीगत सामान (EPCG) योजना में महत्वपूर्ण वृद्धि: निर्यातकों को समर्थन देने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं और स्वचालन शुरू किया गया। • एमनेस्टी योजना: लगभग 954 करोड़ रुपये की धनराशि वसूली गई, लंबित ऑथराइजेशन का समाधान कर नए सिरे से शुरुआत करने में निर्यातकों की सहायता करना।
निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC)	• बाजार पहुंच: चीन को उच्च मूल्य की मछली प्रजातियों का निर्यात शुरू किया गया और रूस को डेयरी/अंडा निर्यात बढ़ाया गया। • उन्नत परीक्षण सुविधाएं: EIA-कोडि में उन्नत खाद्य गुणवत्ता परीक्षण।
व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)	• व्यापार रक्षा: इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और MSME उत्पादों जैसे क्षेत्रों में अनुचित व्यापार गतिविधियों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए गए।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs)	• कौशल विकास: नोएडा SEZ में कैपजेमिनी स्किल सेंटर का लक्ष्य सालाना 1,000 युवाओं को AI, रोबोटिक्स और डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण देना है। • आइसगेट रोलआउट: नॉन-IT/ ITES SEZs इकाइयां RoDTEP योजना के लाभों के लिए आवेदन कर सकती हैं।
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (IIFT)	• दुबई कैंपस: भारत-UAE व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने वाला पहला विदेशी कैंपस स्थापित। • नई पहलें: ○ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता केंद्र ○ भारतीय व्यापार प्रथाओं के दस्तावेजीकरण के लिए केस स्टडी सेंटर।
गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM)	• परिवर्तनकारी विकास: 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का GMV (सकल बाजार मूल्य) रिकॉर्ड किया गया। • समावेशिता: महिलाओं के नेतृत्व वाले MSMEs को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया गया है, 1.69 लाख महिला उद्यमियों को पंजीकृत किया गया है।
व्यापार प्रदर्शन	• समग्र विकास: कुल निर्यात में 7.3% की सकारात्मक वृद्धि देखी गई, वस्तु निर्यात में 3.1% और सेवा निर्यात में 12.7% की वृद्धि हुई। • क्षेत्रवार मुख्य विशेषताएं: ○ कृषि: बासमती चावल (+14.28%), मसाले (+10%), और संबद्ध उत्पादों में लगातार वृद्धि हुई। ○ इंजीनियरिंग सामान: 9.73% बढ़कर 67.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

	○ इलेक्ट्रॉनिक्स: निर्यात में 23.69% की वृद्धि हुई। ○ स्मार्टफोन: 36.85% की वृद्धि दर्ज की गई। ○ सोलर PV: निर्यात लगभग दोगुना हो गया है, अब भारत, विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है। ○ फार्मास्यूटिकल्स: 8% की निरंतर मजबूत वृद्धि। ○ वस्त्र: 11.59% की वृद्धि दर्ज की गई।
भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (ITPO)	• भारत की औद्योगिक और सांस्कृतिक शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों का आयोजन किया।

2.2. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

विषय	प्रमुख पहलें/ उपलब्धियां/ उपाय
उत्पाद-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं	• उद्देश्य: PLI योजनाओं का उद्देश्य भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। • कुल परिव्यय: 1.97 लाख करोड़ रुपये (लगभग 26 बिलियन डॉलर)। • कवर किए गए प्रमुख क्षेत्रक: ○ मोबाइल विनिर्माण और इलेक्ट्रॉनिक घटक ○ ड्रग इंटरमीडियरीज, APIs, और क्रिटिकल की-स्टार्टिंग मटेरियल ○ चिकित्सा उपकरण विनिर्माण ○ ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक ○ दवाइयाँ ○ स्पेशलिटी स्टील ○ दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद ○ इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पाद ○ व्हाइट गुड्स (जैसे- एयर कंडीशनर और LEDs) ○ खाद्य उत्पाद ○ वस्त्र: MMF (मानव निर्मित फाइबर) और तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्स्टाइल) ○ उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल ○ एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरियां ○ ड्रोन और ड्रोन घटक
पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान	• उद्देश्य: यह प्रभावी लॉजिस्टिक योजना के लिए सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, दूरसंचार और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे कई बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से डेटा को एकीकृत करता है। • प्लेटफॉर्म की विशेषताएं: मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के बेहतर समन्वय और योजना निर्माण के लिए एक GIS-सक्षम प्लेटफॉर्म। • वर्तमान स्थिति: ○ 44 मंत्रालय/ विभाग इसमें शामिल किये गये हैं (जिनमें बुनियादी ढांचा, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रक आदि शामिल हैं)। ○ 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने इस प्लेटफॉर्म में योगदान दिया है। ○ कुल 1614 डेटा लेयर्स को एकीकृत किया गया है, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। • प्रमुख क्षेत्रक: बुनियादी ढांचे का विकास, लॉजिस्टिक एकीकरण, परिवहन और सामाजिक क्षेत्रकों के लिए परियोजना प्रबंधन में सुधार।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP)	• लॉन्च: लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में सुधार और अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति शुरू की गई।

	• मुख्य लक्ष्य: ○ लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक मानकों के बराबर लाना। ○ लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक: वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार, 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का लक्ष्य। ○ डेटा-आधारित निर्णय लेना: तथ्यों के आधार पर लॉजिस्टिक्स संबंधी निर्णय लेने के लिए डेटा-आधारित तंत्र की स्थापना करना। • कार्यान्वयन योजना: एक व्यापक लॉजिस्टिक्स कार्य योजना (CLAP) के माध्यम से, जिसमें प्रक्रिया सुधार, बुनियादी ढांचे का विकास और डिजिटलीकरण शामिल है।
मेक इन इंडिया पहल	• लॉन्च: भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और एक मजबूत विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने के लिए 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई और 25 सितंबर 2014 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। • उद्देश्य: इस पहल का उद्देश्य निवेश, नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करके भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है। • फोकस क्षेत्र: ○ भारतीय उद्योग की ताकत, आयात कम करना, निर्यात क्षमता और रोजगार क्षमता के आधार पर 24 उप-क्षेत्रों का चयन किया गया। ○ सरकार के प्रयास इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, वस्त्र और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। • निवेश प्रोत्साहन योजनाएं: 'निवेश प्रोत्साहन योजना' (SIP) के अंतर्गत कई पहले शुरू की गईं, जैसे- ○ NSWS (नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम), ○ PDC (परियोजना विकास प्रकोष्ठ), और ○ ODOP (एक जिला, एक उत्पाद)
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम	• उद्देश्य: मांग से पहले उन्नत बुनियादी ढांचे का विकास करना, जिसका लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना और भारत को वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एक प्रमुख हितधारक के रूप में स्थापित करना है। • प्रमुख कार्य: 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना, उद्योग 4.0 मानकों को लागू करना तथा सामाजिक समानता, लैंगिक समानता और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना। • भावी विस्तार: अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अतिरिक्त ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से 1.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने का अनुमान है।
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)	• बौद्धिक संपदा (IP) गवर्नेंस को मजबूत करना: दस्तावेजों की ई-फाइलिंग, ट्रेडमार्क के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML)-आधारित सर्च सिस्टम और उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए AI-आधारित सार्वजनिक चैटबॉट की शुरुआत सहित IP-संबंधी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के प्रयास किए गए हैं। • विधायी सुधार: स्टार्टअप, SMEs और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पेटेंट परीक्षणों में तेजी लाने के लिए बदलाव किए गए हैं। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फॉर्म सरलीकरण और शुल्क माफी भी शुरू की गई है। • IPR वृद्धि: ○ पेटेंट: 2023-24 में रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट (1,03,057) प्रदान किए गए, जो 2014-15 से उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। ○ ट्रेडमार्क: ट्रेडमार्क पंजीकरण में सात गुना वृद्धि देखी गई। ○ भौगोलिक संकेतक (GI): पंजीकृत भौगोलिक संकेतकों की संख्या बढ़कर 635 हो गई। • वैश्विक स्थिति: वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) में भारत की रैंकिंग 2024 में सुधरकर 39वीं हो गई।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियामक ढांचा	• उद्देश्य: निवेशक-अनुकूल परिवेश का निर्माण, अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति देना। • DPIIT की भूमिका: यह FDI नीति तैयार करता है, जिसे फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत नियमों के माध्यम से लागू किया जाता है।

	• FDI मार्ग: ○ स्वचालित मार्ग: अधिकतर क्षेत्रों में सरकारी मंजूरी की आवश्यकता के बिना 100% FDI की अनुमति है (98% FDI इसी मार्ग से आता है)। ○ सरकारी मार्ग: कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर सामरिक महत्व वाले क्षेत्रों में, FDI के लिए पूर्व-मंजूरी की आवश्यकता होती है। • निषिद्ध FDI क्षेत्र: इसमें लॉटरी व्यवसाय, गैबलिंग, तम्बाकू विनिर्माण, परमाणु ऊर्जा, और निजी निवेश के लिए बंद क्षेत्र शामिल हैं। • सुधार: 2019-2024 के बीच सरकार ने अधिक FDI आकर्षित करने के लिए कोयला, बीमा और रक्षा सहित कई क्षेत्रों को उदार बनाया। • FDI रुझान: 2000 से 2024 तक, भारत को कुल 991 बिलियन अमरीकी डॉलर का FDI प्रवाह प्राप्त हुआ, जिसमें से 67% से अधिक पिछले दशक (2014-2024) में आया। • वित्त वर्ष 2024-25 में FDI प्रवाह: वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में FDI प्रवाह 22.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 26% अधिक है।
स्टार्टअप इंडिया पहल	• उपलब्धियां: ○ देश भर में 1,49,000 से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी गई। ○ लगभग 48% स्टार्टअप्स में कम-से-कम एक महिला निदेशक हैं, और लगभग 50% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित हैं। ○ इन स्टार्टअप्स ने 16 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां उत्पन्न की हैं। • प्रमुख कार्यक्रम: ○ राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देते हैं। ○ भास्कर (BHASKAR) और विनिर्माण इन्क्यूबेशन जैसे कार्यक्रम उत्पाद विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ○ स्टार्टअप महाकुंभ जैसे आयोजन राष्ट्रीय स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
व्यवसाय करने में सुगमता (इज ऑफ डूइंग बिजनेस)	• नियमों के अनुपालन में कमी: भारत ने 42,028 अनुपालन कम किए हैं, जिनकी समीक्षा जारी है और 7,204 अनुपालनों की निगरानी की जा रही है। 2024 में प्रगति के अनुसार कुल अनुपालन में 2% की कमी की जाएगी। • प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाना: जन विश्वास अधिनियम, 2023 के अंतर्गत 42 केंद्रीय अधिनियमों सहित 3,765 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। • राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS): व्यावसायिक मंजूरी को सरल बनाने के लिए 32 मंत्रालयों/ विभागों और 29 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत किया गया। अक्टूबर 2024 तक, 7.10 लाख आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और 4.81 लाख स्वीकृतियाँ दी गई हैं। • व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP) 2024: व्यावसायिक माहौल में सुधार के लिए 344 सुधार (57 केंद्रीय, 287 राज्य) लागू किए गए। • B-रेडी फ्रेमवर्क: विश्व बैंक का B-रेडी फ्रेमवर्क व्यवसाय संचालन में सुधारों में भारत की प्रगति का आकलन करेगा, जिसकी रिपोर्ट अप्रैल 2026 में प्रकाशित की जाएगी।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP)	• उद्देश्य: ODOP 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 780 से अधिक जिलों के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देता है। • समर्थन: केंद्रीय बजट 2023-24 में इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य में PM एकता मॉल के लिए फंड आवंटित किया गया। • राष्ट्रीय ODOP पुरस्कार (2024): 587 जिलों ने भाग लिया, 641 आवेदन प्राप्त हुए।

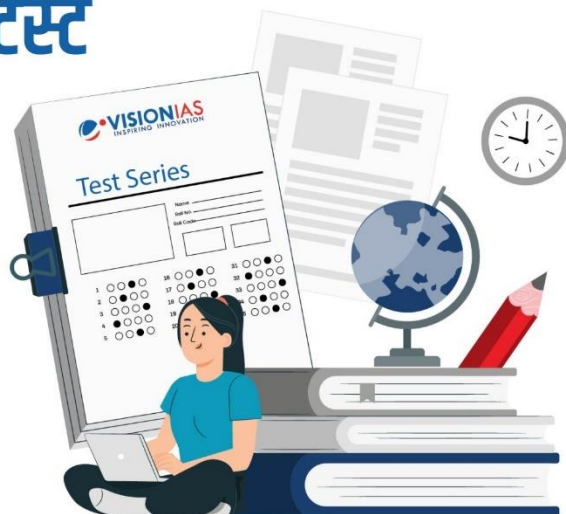
डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC)	- लक्ष्य: ओपन-सोर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से ई-कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण करना और विभिन्न ई-कॉमर्स परिचालनों को मानकीकृत करना। - वृद्धि: सितंबर 2024 में 12.8 मिलियन ऑर्डर दर्ज किए गए, अब तक कुल 113.4 मिलियन ऑर्डर हो गए हैं। - प्रतिभागी: ONDC के 115 सक्रिय प्रतिभागी हैं और यह 7.01 लाख विक्रेताओं के नेटवर्क के साथ 1,100 से अधिक शहरों में कार्य कर रहा है।
औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली (IPRS)	- उद्देश्य: औद्योगिक पार्कों की प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करना और उसे बढ़ावा देना। - प्रदर्शन: 449 पार्कों को रेटिंग दी गई, जिनमें से 41 को "लीडर", 90 को "चैलेंजर" तथा 185 को "एस्पायरर्स" के रूप में मान्यता दी गई।
नई 'केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ'	- जम्मू और कश्मीर औद्योगिक विकास योजना: पूंजी निवेश, GST-लिंकड प्रोत्साहन और ब्याज अनुदान के लिए 28,400 करोड़ रुपये के साथ शुरू की गई। - उत्तर-पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना (उन्नति): पूर्वोत्तर भारत में औद्योगिक विकास के लिए 10,037 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें पिछड़े जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए मौजूदा और नई, दोनों प्रकार की औद्योगिक इकाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।



ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इन्ोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट	
5 फंडामेंटल टेस्ट	15 एप्लाइड टेस्ट
10 फुल लेंथ टेस्ट	



2025	ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY	हिन्दी माध्यम 25 जनवरी	2026	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 2 फरवरी
-------------	--	---	-------------	--	--

3. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)

प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना - पायलट प्रोजेक्ट	- प्रधानमंत्री इंटरनशिप योजना का उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे उन्हें विभिन्न व्यवसायों में वास्तविक जीवन के कारोबारी माहौल से परिचित होने का अवसर मिलेगा। वित्तीय सहायता: इंटरन को हर महीने 5,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से 4,500 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 500 रुपये होस्ट कंपनी द्वारा अपने CSR फंड से दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, जॉइनिंग के समय MCA द्वारा आकस्मिक खर्चों के लिए 6,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। अवधि और प्रगति: 12 महीने की इंटरनशिप 3 अक्टूबर, 2024 को एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुई, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.25 लाख अवसर प्रदान करना है। लगभग 1.27 लाख इंटरनशिप पोस्ट की गई हैं। इनमें लगभग 4.87 लाख युवाओं ने पंजीकरण कराया है और 6.21 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। चयन प्रक्रिया जारी है।
MCA21 का संस्करण-2 से संस्करण-3 में स्थानांतरण	संवर्द्धन: MCA ने अपने अनुपालन प्लेटफॉर्म को संस्करण-2 से संस्करण-3 में अपग्रेड किया है। इससे अनुपालन फॉर्म की संख्या पांच से घटकर तीन हो गई है और फंड ट्रांसफर प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। सभी कंपनी फॉर्म अब स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (STP) में एकीकृत हो गई हैं, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप समाप्त हो गया है। क्लेम्स की ट्रैकिंग और सत्यापन की सुविधा के लिए नोडल अधिकारियों के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है।
जन विश्वास पहल	शेयर हस्तांतरण के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की मान्यता (Recognition of Legal Heirship Certificate for Share Transmission): निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में हस्तांतरित शेयरों के हस्तांतरण को पंजीकृत करने के लिए अब बिना किसी मौद्रिक सीमा के कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाते हैं। इससे उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रशासन के पत्र या वसीयत की प्रोबेट की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यह सुधार सिविल कोर्ट प्रक्रियाओं से जुड़े समय और लागत को कम करता है। खोए हुए शेयर प्रमाण-पत्रों के लिए सरलीकरण: 5 लाख रुपये तक के मूल्य के खोए हुए भौतिक शेयर प्रमाण-पत्रों के लिए FIR दर्ज करने की आवश्यकता को हटा दिया गया है, जिससे दावेदारों के लिए प्रक्रिया सरल हो गई है। जमानत (Surety) आवश्यकताओं की समाप्ति: डुप्लिकेट भौतिक सुरक्षा प्रमाण-पत्रों (duplicate physical security certificates) के लिए आवेदन करते समय जमानत की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, जिससे निवेशकों के लिए आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है।
IEPF द्वारा उन्नत शिकायत निवारण तंत्र	बहुभाषी IVRS सुविधा: निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (IEPFA) ने निवेशकों को बहुभाषी सहायता प्रदान करने, उनकी पहुंच और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बहुभाषी इंटरैक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम (IVRS) की सुविधा के साथ एक उन्नत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) की उपलब्धियां	डिफॉल्ट मामलों का समाधान: IBC ने प्रवेश-पूर्व 10.22 लाख करोड़ रुपये के डिफॉल्ट मामलों को सफलतापूर्वक हल किया है, रिकॉर्ड समाधान दर हासिल की है और वित्तीय स्थिरता में योगदान दिया है। प्रस्ताव: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत प्रक्रियाओं की दक्षता में सुधार के लिए एक एकीकृत प्रौद्योगिकी मंच का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य दिवाला कार्यवाही को सुव्यवस्थित करना और पारदर्शिता बढ़ाना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का प्रदर्शन	संयोजित (कॉम्बिनेशन) मामलों का निपटान: CCI ने सितंबर 2024 तक 99% संयोजन मामलों का निपटान कर दिया है, जो विलय और अधिग्रहण अनुमोदन से निपटने में इसकी दक्षता को दर्शाता है।
सेंद्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) का शुभारंभ	ई-फॉर्म प्रोसेसिंग: राष्ट्रव्यापी ई-फॉर्म प्रोसेसिंग के लिए एक सेंद्रल प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जिससे कॉर्पोरेट फाइलिंग और अनुपालन की दक्षता और गति में वृद्धि होगी।

कॉर्पोरेट व्यवसाय विकास प्रक्रिया में तेजी	• CPACE पहल: कॉर्पोरेट प्रक्रियाएं और स्वचालित अनुपालन वातावरण (CPACE)¹ ने कॉर्पोरेट व्यवसाय विकास के लिए प्रोसेसिंग समय को घटाकर 90 दिन कर दिया है, जिससे कंपनियों का आसान और त्वरित समापन संभव हो गया है।
भारतीय लेखांकन मानकों में संशोधन	• भारतीय लेखा मानक 116 और भारतीय लेखा मानक 117: भारतीय लेखा मानक 116 और 117 में संशोधन किए गए हैं। उन्हें वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाया गया है और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों में सुधार किया गया है।
फेसलेस न्याय-निर्णय तंत्र	• परिचय: गैर-आपराधिक प्रकृति के कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स के लिए एक फेसलेस न्याय निर्णय तंत्र लागू किया गया है, जिससे न्याय निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी। • ये पहल भारत में अनुकूल कॉर्पोरेट माहौल बनाने, व्यवसाय सुगमता बढ़ाने और आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए MCA की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव
असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र



2025	ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY	हिन्दी माध्यम 25 जनवरी
2026	ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY	हिन्दी माध्यम 2 फरवरी



¹ Corporate Processes and Automated Compliance Environment

4. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

बुनियादी ढांचे का विकास	- ट्रैक नवीनीकरण और गति में वृद्धि: - भारतीय रेलवे ने 6,450 किमी ट्रैक नवीनीकरण और 8,550 टर्नआउट नवीनीकरण का कार्य पूरा किया। 2,000 किमी ट्रैक पर गति बढ़ाकर 130 किमी/घंटा कर दी गई, जिससे प्रमुख मार्गों पर दक्षता बढ़ गई। - विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा: 3,210 रूट किलोमीटर (Rkm) का विद्युतीकरण किया गया, जिससे विद्युतीकृत ब्रॉड गेज (BG) नेटवर्क का विस्तार 97% तक हो गया। - नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 2,014 मेगावाट तक पहुंच गई, जो संधारणीय परिचालन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।
रोलिंग स्टॉक और सेवाएँ	- नई रेलगाड़ियों की शुरुआत: 136 बंदे भारत ट्रेनें शुरू की गईं। - पहली नमो भारत रैपिड रेल शुरू की गई।
फ्रेट ऑपरेशन्स	फ्रेट लोडिंग: भारतीय रेलवे ने 2024 में 1,473 मिलियन टन (MT) फ्रेट लोडिंग किया, जो 3.86% की वृद्धि दर्शाता है। पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल गलियारों ने 72,000 से अधिक रेलगाड़ियों को चलाने की सुविधा प्रदान की, जिससे माल ढुलाई दक्षता में सुधार हुआ।
स्टेशन पुनर्विकास	अमृत भारत स्टेशन योजना: इस योजना के अंतर्गत 1,337 स्टेशनों में से 1,198 पर कार्य प्रारंभ हो गया है। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क में यात्री सुविधाओं का आधुनिकीकरण और संवर्धन करना है।
सुरक्षा, दक्षता और यात्री सेवाओं को बढ़ाने के लिए दूरसंचार में प्रगति	- हाथी घुसपैठ पहचान प्रणाली (Elephant Intrusion Detection System: EIDS) - कोच गाइडेंस और ट्रेन इंडिकेटर प्रणालियों का एकीकरण, जिससे यात्रियों को वास्तविक समय पर सूचना मिल सके। - केंद्रीयकृत घोषणा प्रणाली: एक समान और समय पर घोषणाएं प्रदान करने के लिए भोपाल मंडल (पश्चिम मध्य रेलवे) और दीन दयाल उपाध्याय मंडल (पूर्व मध्य रेलवे) के सभी स्टेशनों पर स्थापित की गई। - डिजिटल VHF संचार को अपनाना: लोकोमोटिव पायलटों और गाड़ों के बीच संचार में सुधार के लिए डिजिटल 5W बॉकी-टॉकी सेट की खरीद अनिवार्य की गई। - सुरंग संचार प्रणाली: चुनौतीपूर्ण इलाकों में निर्बाध संचार बनाए रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे सुरंगों के भीतर संचार प्रणाली स्थापित करने के लिए परियोजनाएं शुरू की गईं। - ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) नेटवर्क का विस्तार - रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा: 6,112 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। - CCTV कैमरों की स्थापना: सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1,051 स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं तथा हॉल्ट स्टेशनों को छोड़कर सभी स्टेशनों तक कवरेज बढ़ाने की योजना है।
सुरक्षा संवर्द्धन	- कवच सुरक्षा प्रौद्योगिकी: - स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच स्थापित करने के प्रयास चल रहे हैं। - तकनीशियनों को प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही, इस प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के विस्तार के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं।
विरासत संरक्षण और पर्यटन	- विरासत स्थलों का डिजिटलीकरण: भारतीय रेलवे ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करते हुए 80 स्टेशनों और ऐतिहासिक महत्व के 78 ढांचों का डिजिटलीकरण किया। - सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए घूम महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए।

रेलवे सुरक्षा पहलें (2024)

- ऑपरेशन नन्हे फरिस्ते: बच्चों का बचाव।
- ऑपरेशन यात्री सुरक्षा: यात्रियों की सुरक्षा संबंधी शिकायतों का निवारण।
- ऑपरेशन अमानत: छूटे हुए सामान की प्राप्ति और वापसी।
- ऑपरेशन जीवन रक्षा: पटरियों पर जोखिम में पड़े यात्रियों की जान बचाना।
- ऑपरेशन सेवा: बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों और बीमार यात्रियों को सहायता।
- ऑपरेशन मातृशक्ति: रेल यात्रा के दौरान प्रसव में सहायता।
- ऑपरेशन AAHT: मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई।
- ऑपरेशन उपलब्ध: अनाधिकृत टिकट और प्रवेश के खिलाफ कार्रवाई।
- ऑपरेशन रेल सुरक्षा: रेलवे संपत्ति की सुरक्षा।
- ऑपरेशन सतर्क: प्रतिबंधित और लावारिस वस्तुओं की बरामदगी में कानून प्रवर्तन को सहायता प्रदान करना।
- ऑपरेशन दूसरा: अनाधिकृत हॉकिंग और वेंडिंग के खिलाफ कार्रवाई।
- ऑपरेशन NARCOS: मादक पदार्थों और ड्रग्स से संबंधित गिरफ्तारियां।
- ऑपरेशन विलेप (WILEP): अवैध वन्यजीव व्यापार के खिलाफ कार्रवाई।
- ऑपरेशन भूमि: रेलवे की भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराना।
- मेरी सहेली पहल: अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों के लिए सुरक्षा।


Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- » UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 20,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- » अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- » परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- » टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक



अधिक जानकारी
के लिए दिए गए
QR कोड को
स्कैन कीजिए

2025
**ENGLISH MEDIUM
25 JANUARY**
**हिन्दी माध्यम
25 जनवरी**
2026
**ENGLISH MEDIUM
19 JANUARY**
**हिन्दी माध्यम
2 फरवरी**

5. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology: MeitY)

सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम	भारत सरकार ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में चार (4) सेमीकंडक्टर निर्माण इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी है।
इंडियाAI मिशन	- MeitY ने इंडियाAI मिशन को निम्नलिखित प्रमुख पहलों के साथ आगे बढ़ाया है: राष्ट्रीय AI पोर्टल (INDIAai): यह MeitY, NeGD और NASSCOM का एक संयुक्त प्रयास है। यह भारत में AI के विकास के लिए व्यापक संसाधन प्रदान करता है। AI रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म (AIRAWAT): सरकार ने AI अनुसंधान और ज्ञान के समावेशन के लिए एक साझा कंप्यूट प्लेटफॉर्म परियोजना शुरू की है। यह 200 पेटाफ्लॉप्स मिक्स्ड प्रिसिजन AI मशीन के साथ प्रूफ ऑफ कांसेप्ट (PoC) के रूप में विकसित एक प्लेटफॉर्म है, जिसे 790 AI पेटाफ्लॉप्स तक बढ़ाया जा सकता है।
कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता	डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास में की गई उल्लेखनीय प्रगति: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA): इसके तहत 6.39 करोड़ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। यह निर्धारित 6 करोड़ के लक्ष्य से अधिक है। इससे ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता में वृद्धि हुई है। कौशल विकास प्रशिक्षण: 81 आकांक्षी जिलों में 18,209 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिलाओं) के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर बढ़े हैं।
भाषा सुलभता	भाषिणी पहल के तहत 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में अनुवाद सेवाएं उपलब्ध करा के भाषाई बाधाओं को दूर किया गया है। साथ ही प्रति माह 10 करोड़ से अधिक इनफेरेंस प्रदान करके डिजिटल सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सुलभ बनाया गया है।
सुपरकंप्यूटिंग अवसंरचना	प्रधानमंत्री ने तीन PARAM रुद्र सुपरकंप्यूटर लॉन्च किए हैं। इससे भौतिकी, पृथ्वी विज्ञान, और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को मजबूती मिलने के साथ-साथ भारत की कम्प्युटेशनल क्षमता को भी बढ़ावा मिला है।
2024 में लागू की गई नीतियां और संशोधन	- CCTV कैमरों के लिए व्यापक नियामक आदेश (CRO) के तहत नए नियम अक्टूबर 2024 से प्रभावी हुए हैं। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला अधिसूचना: आई.टी. अधिनियम 2000 की धारा 79A के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए 15 फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया है।
डिजिटल अवसंरचना	डेटा सेंटर्स: क्षमता में वृद्धि और आपदा प्रबंधन सेवाओं के जरिए राष्ट्रीय डेटा सेंटर्स का विस्तार किया गया है। क्लाउड सेवाएं: NIC की मेघराज परियोजना 300 से अधिक सरकारी विभागों को सहायता प्रदान करती है। इससे आई.टी. अवसंरचना के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिला है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: आधार, UPI और डिजिलॉकर जैसी पहलों ने सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल बनाया है। UPI: 2024 के मध्य तक UPI से 24,100 करोड़ लेन-देन संपन्न किए गए।
नागरिक केंद्रित सेवाएँ	उमंग: 2,000 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है, नागरिक जुड़ाव को सुलभ बनाता है। मेरी पहचान: यह सेवाओं तक निर्बाध पहुंच के लिए राष्ट्रीय सिंगल साइन-ऑन प्लेटफॉर्म है। ई-हस्ताक्षर: डिजिटल हस्ताक्षर सेवा प्रदान करती है। इसके तहत 81 करोड़ से अधिक ई-साइन जारी किए गए हैं।

क्रांतिकारी सरकारी संचालन	- डिजिटलॉकर: दस्तावेजों को डिजिटल रूप में जारी करने और उसके सत्यापन को सुगम बनाता है। - कोलैब फाइल्स & Gov ड्राइव: यह सरकारी अधिकारियों के बीच सुरक्षित दस्तावेज प्रबंधन और उनके साझाकरण के लिए एक क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है।
आगामी योजनाएं	- सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम: PLI योजनाओं के माध्यम से भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाना। - AI विकास: इंडियाAI मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में AI अनुसंधान और उसके अनुप्रयोग पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। - डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विस्तार: आधार, UPI और डिजिटलॉकर को और अधिक सुरक्षित बनाना। - साइबर सुरक्षा: मजबूत साइबर सुरक्षा के लिए साझेदारी और उन्नत प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना।



हिंदी और अंग्रेजी
माध्यम

प्रवेश प्रारंभ

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की विशेषताएं



प्री-DAF सेशन: यह DAF में मरे जाने वाले एक-एक पॉइंट की सहायता समझ और व्यक्तित्व के वांछित गुणों को प्रतिबिंबित करने के लिए साक्षात्कारीपूर्वक DAF एंट्री में सहायक है।



मॉक इंटरव्यू सेशन: व्यक्तित्व परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सोनियर एक्सपर्ट्स और फैंकल्टी मेंबर्स, भूतपूर्व व्यूरोक्रेट्स एवं शिक्षाविदों के साथ मॉक इंटरव्यू सेशन।



टॉपर्स और कार्यरत व्यूरोक्रेट्स के साथ इंटरैक्शन: प्रश्नों के ठोस समाधान, इंटरैक्टिव लर्निंग एवं टॉपर्स और कार्यरत व्यूरोक्रेट्स के अनुभव से प्रेरणा लेने के लिए इंटरैक्टिव सेशन।



DAF एनालिसिस सेशन: अपेक्षित प्रश्नों एवं उनके उत्तरों के बारे में सोनियर एक्सपर्ट्स और फैंकल्टी मेंबर्स के साथ DAF को लेकर गहन विश्लेषण और चर्चा।



व्यक्तिगत मेंटरशिप और मार्गदर्शन: हमारे डेवेलपमेंट सोनियर एक्सपर्ट्स के सहयोग से व्यक्तित्व परीक्षा की समग्र तैयारी व बेहतर प्रबंधन तथा अपने प्रदर्शन को अधिकतम करना।



प्रदर्शन का मूल्यांकन और फीडबैक: अपने मजबूत एवं सुधार करने वाले पक्षों की पहचान करने के साथ-साथ उनमें आगे और सुधार करने एवं उन्हें बेहतर बनाने के लिए पोजिटिव फीडबैक।



एलोव्यूशन सेशन: इसमें डिस्कशन और पीयर लर्निंग की सहायता से कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने तथा उसे बेहतर बनाने एवं व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास किया जाएगा।



करेंट अफेयर्स की कक्षाएं: करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक व्यापक और विरलेपणालक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।



मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग: स्व-मूल्यांकन के लिए इंटरव्यू सेशन का वीडियो भी दिया जाएगा।



Scan QR CODE to watch How to Prepare for UPSC Personality Test

DAF एनालिसिस और मॉक इंटरव्यू से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करें

7042413505, 9354559299
interview@visionias.in

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए
or dksM स्कैन करें



6. खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय (Ministry of Food Processing)

विषय	प्रमुख पहलें/ उपलब्धियां/ उपाय
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक में उपलब्धियां	- निर्यात संवृद्धि: कृषि खाद्य निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की हिस्सेदारी 13.7% (2014-15) से बढ़कर 23.4% (2023-24) हो गई है। - रोजगार सृजन: औद्योगिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, संगठित विनिर्माण क्षेत्रक में मौजूद कुल रोजगार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की हिस्सेदारी 12.41% है। - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): अप्रैल 2014 से मार्च 2024 तक इस क्षेत्रक ने 6.793 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। - आर्थिक प्रभाव: खाद्य प्रसंस्करण में सकल मूल्य वर्धन (GVA) 1.34 लाख करोड़ रुपये (2014-15) से बढ़कर 1.92 लाख करोड़ रुपये (2022-23) हो गया है।
बजट और वित्तीय सहायता	- आवंटन में वृद्धि: मंत्रालय के बजट में 30.19% की वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3,290 करोड़ तक पहुँच गया है। - क्रेडिट-लिंकड सब्सिडी: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) के तहत जनवरी 2024 से अब तक 46,643 ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
प्रमुख योजनाएं और पहलें	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) - इस योजना के तहत कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनसे विशेष रूप से मत्स्य पालन और डेयरी क्षेत्रकों के मामले में लगभग 7.46 लाख नौकरियां सृजित होने और उचित मूल्य प्राप्त होने व अपव्यय में कमी के जरिए कृषिगत आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। - कई कोल्ड चेन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिससे मत्स्य अपव्यय में 70% और डेयरी उत्पाद अपव्यय में 85% की कमी आई है। - बहुउद्देश्यीय खाद्य विकिरण परियोजना शुरू की गई है। इसके साथ ही, 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, जिन्हें NABL से मान्यता प्राप्त होगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (PMFME) - इसके तहत लगभग 1,14,388 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे व्यक्तियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और सहकारी समितियों को लाभ हुआ है। - SHGs के 3.10 लाख सदस्यों को 1,032.31 करोड़ रुपये की आरंभिक पूंजी (seed capital) का वितरण किया गया है। - ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता: स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए NAFED की राष्ट्रीय-स्तर की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन योजना (PLISFPI) निवेश और रोजगार: - इस योजना के तहत 8,910 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जिससे 2.89 लाख नौकरियां सृजित हुईं। - पात्र परियोजनाओं के लिए 1,084.01 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन वितरित किया गया है। मिलेट-आधारित उत्पाद: - घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में RTC/ RTE मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए मिलेट-आधारित उत्पादों हेतु एक विशेष घटक पेश शुरू किया गया है।
जागरूकता और क्षमता निर्माण	ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट (GFRS): इसे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के एक हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। इसने वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानकों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया है।

7. मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)

7.1. पशुपालन और डेयरी विभाग (Department of Animal Husbandry and Dairying)

क्षेत्रक में संवृद्धि	- पशुधन क्षेत्रक ने 2022-23 में (चालू कीमतों पर) कुल GVA में 5.50% का योगदान दिया। - विश्व में भारत की रैंकिंग - दूध उत्पादन में प्रथम। - अंडा उत्पादन में दूसरा स्थान। - विश्व में मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर।
पशुपालन और डेयरी योजनाएं	- राष्ट्रीय गोकुल मिशन: स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण तथा गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन पर केंद्रित। 2024 में शुरू की गई पहलें: - स्वदेशी रूप से विकसित सेक्स-सॉर्टेड सीमेन उत्पादन तकनीक - इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के लिए स्वदेशी माध्यम - मवेशियों के लिए सामान्य जीनोमिक चिप गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप - पशुधन उत्पादों के लिए ट्रेसिबिलिटी प्लेटफॉर्म
योजनाएं	- राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD): इसका उद्देश्य दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और मार्केटिंग को बढ़ाना है। - यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। - डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) - डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता: पात्र भागीदार एजेंसियों (PAs) द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ली गई कार्यशील पूंजी ऋण पर प्रतिवर्ष 2% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाता है। - राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM): इसका उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि तथा मांस, बकरी का दूध, अंडा और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। - पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF): इसका उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं को डेयरी प्रसंस्करण, मांस प्रसंस्करण, पशु आहार आदि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
अन्य पहलें	- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम: इसका उद्देश्य पशुधन संबंधी रोगों का समाधान करना तथा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को बढ़ाना है। - राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (2019): इसके तहत 2030 तक मुंहपका और खुरपका एवं ब्रुसेल्लोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। - चलित पशु चिकित्सा इकाइयाँ टोल-फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किसानों के घर पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं। - पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता। - आर्थिक रूप से नुकसान देह और जूनोटिक बीमारियों, जैसे- लम्पी स्किन डिजीज के टीकाकरण के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान की गई है। - पशु चिकित्सा शिक्षा के लिए कॉलेजों के नेटवर्क का विस्तार किया गया है।
पशुधन गणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण योजना	- एकीकृत नमूना सर्वेक्षण: दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों (MLP) का अनुमान लगाना। - पशुधन गणना: 21वीं पशुधन गणना शुरू की गई है। - दुग्ध सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक कंपनियों के डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)।

8. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

8.1. ग्रामीण विकास विभाग (Department of Rural Development)

थीम्स	प्रमुख पहलें/ उपलब्धियां/ उपाय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)	- उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को प्रतिवर्ष कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी युक्त रोजगार के माध्यम से आजीविका की सुरक्षा प्रदान करना। - प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति: - राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सेवा (NMMS): उपस्थिति पर नज़र रखने के लिए जियो-टैग, टाइम-स्टैम्प फोटोग्राफ। - GIS-आधारित नियोजन (युक्तधारा): रिज-टू-वैली दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए सैचुरेशन-बेस्ड ग्राम पंचायत योजनाओं के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग। - जियो-मनरेगा: तीन-चरणीय जियो-टैगिंग के माध्यम से परिसंपत्ति निर्माण पर नज़र रखी जाती है; अब तक 6.13 करोड़ परिसंपत्तियों को टैग किया गया है। - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का कार्यान्वयन: आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के माध्यम से 99% से अधिक मजदूरी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है; सक्रिय श्रमिकों में से 99.49% को आधार से जोड़ा जा चुका है।
प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G)	- उद्देश्य: 2024 तक "सभी के लिए आवास" तथा ग्रामीण परिवारों के लिए पक्के मकान। - उपलब्धियां: 3.33 करोड़ मकान आवंटित किये गये हैं, 3.22 करोड़ स्वीकृत किये गये तथा 2.68 करोड़ पूरे किये गये। - विस्तार: वित्त वर्ष 2024-29 के दौरान, अतिरिक्त 2 करोड़ घरों के निर्माण की योजना बनाई गई है। - तकनीकी नवाचार: - आवास + 2024 ऐप: सर्वेक्षण, चेहरा प्रमाणीकरण और जियो-टैग फोटो के लिए। - AI/ ML का उपयोग: धोखाधड़ी की रोकथाम, विसंगति का पता लगाने और फोटो के सत्यापन के लिए अनुशंसा प्रणाली (Recommendation systems)। - आवास सखी ऐप: PMAY-G के बारे में जागरूकता और पहुंच को बढ़ावा देना।
प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)	- उद्देश्य: पात्र बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ना। - उपलब्धियां: 7.70 लाख किमी से अधिक लंबाई की सड़कों और 9,257 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। - वित्त वर्ष 2024: 19,606 कि.मी. सड़कें और 3,489 पुल पूरे किए जा चुके हैं। - PMGSY-IV का लक्ष्य 25,000 बस्तियों के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाना है (वित्त वर्ष 2024-29)।
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)	- उद्देश्य: लाभकारी रोजगार और स्थायी आजीविका के माध्यम से गरीबी को कम करना। - मुख्य घटक: - संस्थागत निर्माण: 6 लाख कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (CRPs) को प्रशिक्षित किया गया है; सामूहिक सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूह (SHGs), ग्राम संगठन (VOs), और क्लस्टर स्तरीय संघ (CLFs) की स्थापना की गई है। - सामाजिक समावेशन: स्वच्छ भारत मिशन, पोषण अभियान के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन अभियान आदि चलाए गए हैं।

	○ वित्तीय समावेशन: 1.35 लाख SHGs सदस्यों को बैंकिंग सेवाओं के लिए बैंकिंग करेस्पॉण्डेंट सखी के रूप में नियुक्त किया गया है। ○ आजीविका: ■ कृषि क्षेत्रक: महिला किसानों के लिए कृषि-पारिस्थितिकी पद्धतियों और बाजार तक पहुंच प्रदान की गई है। ■ गैर-कृषि क्षेत्रक: हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण आदि में सूक्ष्म उद्यमों के लिए समर्थन दिया गया है। ● लखपति दीदी पहल: 3 करोड़ महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये कमाने के लिए सशक्त बनाया गया है; 1.15 करोड़ लखपति दीदी बनाई गई है।
मिशन अमृत सरोवर	● उद्देश्य: प्रत्येक ग्रामीण जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण या उनका पुनरुद्धार कर जल संरक्षण को बढ़ावा देना। ● उपलब्धियां: ○ अब तक 68,000 से अधिक सरोवरों का निर्माण किया गया है, जिनमें से 46,000 का निर्माण मनरेगा के तहत किया गया है।
PM-जनमन	● उद्देश्य: PVTG परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, कनेक्टिविटी, स्वच्छ जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संधारणीय आजीविका प्रदान करना। ● उपलब्धियां: PMAY-G के अंतर्गत 3.47 लाख घर स्वीकृत किए गए हैं और इनमें से 70,905 घर पूरे किए जा चुके हैं।

8.2. भूमि संसाधन विभाग (Department of Land Resources)

थीम्स	प्रमुख पहलें/ उपलब्धियां/ उपाय
नक्शा कार्यक्रम	● डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा/ NAKSHA) पहल शुरू की गई है। ● उद्देश्य: देश भर के 150 शहरों के लिए भूमि स्वामित्व को स्पष्ट करने और विवादों का समाधान करने हेतु शहरी भूमि अभिलेखों का निर्माण करना। ● कार्यान्वयन: इसका कार्यान्वयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व और शहरी विकास विभागों के सहयोग से किया जाता है। ● पूरा करने की समय-सीमा: एक वर्ष के भीतर अपेक्षित।
डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP):	● विस्तार: इसे भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण तथा पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ● कुल वित्तीय सहायता: 2008-09 से 2024-25 तक ₹2,428 करोड़ वितरित किए गए। ● उपलब्धियां: ○ अधिकारों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण: कुछ पूर्वोत्तर राज्यों और लद्दाख को छोड़कर, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में 98.5% तक हासिल किया जा चुका है। ○ मानचित्रों/ FMBs (फिल्ड मेज़रमेंट बुक्स) का डिजिटलीकरण: 95% मानचित्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। ○ भूकर मानचित्रों को अभिलेखों से जोड़ने का कार्य: यह कार्य 72% गांवों में पूरा हो चुका है। ○ पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण: 96% उप-पंजीकरण कार्यालय (SROs) कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं। ○ राजस्व एवं पंजीकरण अभिलेख एकीकरण: 89% उप-पंजीकरण कार्यालय (SROs) में पूरा हो गया।

	○ विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (ULPIN): यह विशिष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए 23 करोड़ भू-खण्डों को आवंटित किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वाटरशेड विकास घटक	● उद्देश्य: कृषि उत्पादकता और ग्रामीण आजीविका में सुधार करते हुए भूमि क्षरण, जल की कमी और मृदा क्षरण जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना। ● 2021-26 के लिए वित्तीय परिव्यय: 49.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए 8,134 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ● उपलब्धियां: ○ जल संचयन संरचनाएं: 1.15 लाख संरचनाओं का निर्माण या उनका पुनरुद्धार किया गया है। ○ सुरक्षात्मक सिंचाई: 1.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है। ○ लाभान्वित किसान: 9.86 लाख किसान सीधे लाभान्वित हुए हैं। ● स्प्रिंग शेड प्रबंधन: 15 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में जल के 4,075 प्राकृतिक स्रोतों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ○ पायलट इनिशिएटिव: 2,740 जल के प्राकृतिक स्रोत स्प्रिंग्स का सफल पुनरुद्धार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप निर्वहन मात्रा और अवधि में वृद्धि हुई। ○ भावी विस्तार की योजना: पायलट इनिशिएटिव के परिणामों के आधार पर जल के प्राकृतिक स्रोत स्प्रिंग्स का पुनरुद्धार किया जाना है।


लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2025
28 जनवरी 2025

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 7 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- ठोस प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2025 के लिए रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु 7 माह का कार्यक्रम)


- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय-वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022
ENQUIRY@VISIONIAS.IN
/VISION_IAS
WWW.VISIONIAS.IN
/C/VISIONIASDELHI
VISION_IAS
/VISIONIAS_UPSC

9. श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

विषय	प्रमुख पहलें/उपलब्धियां/उपाय
ई- श्रम	- ई-श्रम पोर्टल को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक "वन-स्टॉप सॉल्यूशन" के रूप में विकसित किया गया है। ई-श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। - ई-श्रम के साथ 12 सामाजिक सुरक्षा/ कल्याण योजनाओं को जोड़ा गया है। जैसे-एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) आदि। - एग्रीगेटर्स के माध्यम से ई-श्रम पर पंजीकृत प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सत्यापन की सुविधा के लिए ई-श्रम पर एक प्लेटफॉर्म वर्कर्स मॉड्यूल विकसित किया गया है।
राष्ट्रीय कैरियर सेवा	इसे निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन जॉब फेयर्स, कौशल/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी सहित सभी कैरियर संबंधी सेवाओं के लिए एक 'वन स्टॉप प्लेटफॉर्म' के रूप में शुरू किया गया है।
श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन	- मंत्रालय राज्यों में श्रम संहिताओं के तहत नियमों के सामंजस्य पर लगातार काम कर रहा है। - श्रम कानूनों में चार सुधारों की पहचान की गई है, जैसे एकल पंजीकरण, एकल रिटर्न, 5 साल की वैधता के साथ फर्म-आधारित सामान्य लाइसेंस। इसके अलावा मंत्रालय इंस्पेक्टर की भूमिका को इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटर्स में बदलने के लिए भी काम कर रहा है।
गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर	- मंत्रालय गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज हेतु रूपरेखा के विकास की दिशा में काम कर रहा है। - सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की व्यापक समझ विकसित करने और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा फ्रेमवर्क के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु व्यापक हितधारक परामर्श आयोजित किए गए थे।
रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना	- केंद्रीय बजट 2024-25 में शुरू की गई रोजगार से संबद्ध प्रोत्साहन (ELI) योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार को औपचारिक बनाना और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। - इसके तहत एम्प्लॉयबिलिटी, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, जिससे पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26	- ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 से पता चलता है कि भारत ने अपने सामाजिक सुरक्षा कवरेज अनुमान को दोगुना कर दिया है। - रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी कानूनी रूप से बाध्यकारी सामाजिक सहायता योजनाओं में से एक है, जो लगभग 800 मिलियन लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है।



VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

2025	ENGLISH MEDIUM 25 JANUARY	हिन्दी माध्यम 25 जनवरी	2026	ENGLISH MEDIUM 19 JANUARY	हिन्दी माध्यम 2 फरवरी
-------------	--	---	-------------	--	--

10. शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education)

10.1. स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education & Literacy)

विषय	प्रमुख पहलें/उपलब्धियां/उपाय
समग्र शिक्षा	- उद्देश्य: यह SDG-4 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक एकीकृत योजना है। - प्रमुख गतिविधियां: - उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूल खोलना और उन्हें बेहतर बनाना। - स्कूल के भवनों, अतिरिक्त क्लास रूम और छात्रावासों का निर्माण करना। - हाशिये पर मौजूद समुदायों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना करना, जैसे- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। - नामांकन अभियान, स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायता (सहायक उपकरण सहित)। - स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास, निःशुल्क यूनिफार्म और पाठ्य-पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता।
उभरते भारत के लिए पी.एम. स्कूल (पीएम श्री)	- उद्देश्य: देश भर में 14,500 से अधिक स्कूल स्थापित करना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को लागू करना और अन्य स्कूलों के लिए एक बेहतर उदाहरण स्थापित करना। - विवरण : - स्कूलों का चयन 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाता है। - इसके तहत KVS/ NVS सहित कुल 12,000 से अधिक स्कूलों का चयन किया गया है। - स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, लैब और खेल अवसंरचना सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। - फोकस क्षेत्र : - प्राथमिक एवं प्रारम्भिक विद्यालय: बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, आउटडोर खेल सामग्री। - माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय: विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं, कौशल प्रयोगशालाएं।
पी.एम. पोषण (पहले इसका नाम मध्याह्न भोजन योजना था)	- उद्देश्य: सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री-स्कूल से कक्षा आठ तक के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना, बच्चों के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित करना और स्कूल में नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना। - प्रमुख विशेषताएं: तिथि भोजन: विशेष अवसरों पर भोजन के लिए सामुदायिक भागीदारी। स्कूल पोषण उद्यान एनीमिया प्रभावित जिलों और आकांक्षी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। - बेहतर स्थानीय खाद्य स्रोत के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FAOs) और महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना। सोशल ऑडिट: पारदर्शिता के लिए इसे सभी जिलों में अनिवार्य बनाया गया है। पी.एम. पोषण के तहत नवीन दृष्टिकोण: स्कूल पोषण उद्यानों का विकास: यह छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है तथा भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करता है। एनीमिया प्रवण क्षेत्रों के लिए विशेष पोषण: एनीमिया के उच्च प्रसार वाले जिलों को पूरक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं। स्थानीय व्यंजन प्रतियोगिताएं: बेहतर पोषण के लिए क्षेत्रीय और स्थानीय मेनू में नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं।

उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ)	- उद्देश्य: 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्कों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप है, जो सभी के लिए आजीवन सीखने और साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करती है। यह योजना 2022-2027 तक जारी रहेगी, जिसमें हाइब्रिड मॉडल (ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित) का उपयोग किया जाता है। - योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना - घटक: - मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान - महत्वपूर्ण लाइफ स्किल - बुनियादी शिक्षा - प्रोफेशनल या व्यावसायिक कौशल - सतत शिक्षा - कुल बजट: 1,037.9 करोड़ रुपये (केंद्र सरकार का हिस्सा: 700 करोड़, राज्य सरकार का हिस्सा: 337.90 करोड़ रुपये) - उपलब्धियां : - उल्लास मोबाइल ऐप जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। 2 करोड़ शिक्षार्थी (learners) और 39 लाख स्वयंसेवी शिक्षक पंजीकृत। - लक्षांश उल्लास के तहत पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बन गया (जून 2024)।
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS)	- उद्देश्य: आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने और छात्रों को माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। यह योजना हर साल 1 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, जो कक्षा 9 से 12 तक जारी रहती हैं। - छात्रवृत्ति राशि : 12,000 रुपये प्रति वर्ष। - कुल आवंटन (2021-2026) : 1,827 करोड़ रुपये। - उपलब्धियां (2023-24): 300.10 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 2,50,089 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं।
पी.एम.- जनमन (प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान)	- लॉन्च: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह अभियान 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य 18 राज्यों और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) का विकास करना है। - नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA), जिसमें शिक्षा मंत्रालय समग्र शिक्षा योजना के तहत इस अभियान में भाग ले रहा है। - मुख्य फोकस: समग्र सरकार दृष्टिकोण के माध्यम से शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करना। - मुख्य उपलब्धियां: 2023-24: 100 छात्रावासों के लिए स्वीकृत 57.6 करोड़ रुपये में से 24.22 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 2024-25: 19 छात्रावासों के लिए 45 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही पूरक वित्त पोषण के तहत 75 छात्रावासों के लिए अतिरिक्त 188.99 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
दा जगुआ (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान)	- यह योजना स्वास्थ्य, सामाजिक अवसंरचना, आजीविका और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान देकर जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने पर केंद्रित है। - यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक जारी रहेगी और इसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय के माध्यम से गांवों में जनजातीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। - इस योजना के तहत शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1,000 छात्रावासों का निर्माण करना शामिल है।

2024 के लिए विभाग की महत्वपूर्ण पहलें	• बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक - ज्ञान ○ निपुण भारत मिशन: इसे 2021 में शुरू किया गया था, इस राष्ट्रीय मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि 2026-27 तक सभी बच्चे कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक - ज्ञान प्राप्त कर सकें। • परख एवं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण ○ सभी स्कूल बोर्डों में विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान के प्रदर्शन का मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की गई है। ○ परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024: 4 दिसंबर 2024 को आयोजित इस सर्वेक्षण में कक्षा 3, 6 और 9 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें 88,000 स्कूलों के 23 लाख विद्यार्थी शामिल थे। • बहुभाषावाद (Multilingualism) ○ NEP 2020 में मातृभाषा आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है और प्रारंभिक शिक्षा को समर्थन देने के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में 104 प्राइमर विकसित किए गए हैं। दिसंबर 2024 में भारतीय भाषा उत्सव के दौरान 25 नई भाषाओं में प्राइमर जारी किए गए। • पाठ्य-पुस्तकें ○ NCERT ने बालवाटिका से कक्षा 6 तक के लिए सामर्थ्य-आधारित पाठ्य-पुस्तकें (हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रिंट और डिजिटल स्वरूप में विकसित की हैं। ○ कक्षा 4, 5, 7 और 8 के लिए नई पाठ्य-पुस्तकें विकसित की जा रही हैं, तथा कक्षा 9, 10 और 12 के लिए पाठ्य-पुस्तकें 2025 और 2027 के बीच जारी की जाएंगी। • एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ○ NEP 2020 ने अच्छी तरह से प्रशिक्षित, योग्य शिक्षकों को तैयार करने के लिए 64 संस्थानों में 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (ITEP) की शुरुआत की है। इसमें प्रवेश राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (NCET) के माध्यम से होता है। • NPST और NMM ○ राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (NMM): इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए मेंटर्स का एक समूह तैयार करना है। ○ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स (NPST): यह प्रदर्शन संबंधी दिशा-निर्देश प्रदान करके शिक्षकों के व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
स्कूलों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए उठाए गए कदम	• परख (PARAKH) सीखने के परिणामों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है और इसके तहत समग्र प्रगति कार्ड (Holistic Progress Card) और राष्ट्रीय सर्वेक्षण जैसी पहलें शुरू की जा रही हैं, जो छात्र-छात्राओं की दक्षताओं का आकलन करती हैं। • परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण से सीखने या लर्निंग के दौरान सामने आने वाली बाधाओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए लक्षित हस्तक्षेपों की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।
स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) का प्रतिशत सुधारने के लिए उठाए गए कदम	• समावेशी शिक्षा घटक: समग्र शिक्षा कार्यक्रम समर्पित समावेशी शिक्षा (IE) घटक के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) का समर्थन करता है, जो उनकी प्री-स्कूल से कक्षा XII तक भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह हस्तक्षेप, वित्तीय सहायता और विशेष शिक्षक प्रशिक्षण, पहचान शिविर और स्कूलों में सुलभ अवसरचना जैसे संसाधन प्रदान करता है। • पहचान और जांच: "प्रशस्त" दिव्यांगता जांच चेकलिस्ट जैसे साधन हस्तक्षेप के लिए CwSN की प्रारंभिक पहचान करने में मदद करते हैं। इसमें प्रमाणन और संसाधन केंद्रों के माध्यम से आगे की सहायता भी शामिल है। • उन्नत अवसरचना: स्कूलों को रैम्प, हैंडरेल और CwSN के अनुकूल शौचालयों की स्थापना करके अधिक सुलभ बनाया जा रहा है। • वित्तीय सहायता: दिव्यांग लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विशेष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। • शैक्षिक सामग्री की उपलब्धता: NCERT की पाठ्य-पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा (Indian Sign Language) में तब्दील किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रवण संबंधी दिव्यांगता वाले छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो सके।

	छूट और सहूलियत: CBSE, CwSN के लिए वैकल्पिक प्रश्न-पत्र और विषय चयन में सहूलियत जैसी छूट प्रदान करता है।
पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में विभिन्न राज्य स्कूल बोर्डों के बीच समानता लाने के लिए उठाए गए कदम	- परख (PARAKH) की स्थापना: भारत में स्कूल बोर्ड्स में मूल्यांकन प्रणालियों और पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने के लिए NCERT के तहत राष्ट्रीय शिक्षा मूल्यांकन केंद्र (परख) की स्थापना की गई है। - प्रश्न-पत्र टेम्पलेट्स पर कार्यशालाएं: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन करने के लिए प्रश्न-पत्र टेम्पलेट्स का मानकीकरण शुरू किया गया, जिससे सभी बोर्ड्स में मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
APAAR ID – लागू होने संबंधी स्थिति	- APAAR ID: छात्रों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने में मदद करती है और संस्थानों के बीच सुगम स्थानांतरण सुनिश्चित करती है। - लागू करने की स्थिति: दिसंबर 2024 तक, 7 करोड़ से अधिक APAAR ID जारी की जा चुकी हैं, जो छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने में सहायक होंगी।
मिशन लाइफ के लिए इको क्लब के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग पर राज्यों में जागरूकता का प्रसार करना	- मिशन लाइफ: पर्यावरण जागरूकता और संधारणीय पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, इको क्लब को NEP 2020 के तहत मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन-शैली) के साथ एकीकृत किया गया है। - गतिविधियां: वृक्षारोपण, अपशिष्ट की मात्रा को कम करना और जल संरक्षण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। - इको क्लब का प्रभाव : # एकपेड़माकिनाम पहल के तहत लगाए गए 5.18 करोड़ पौधों सहित उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ 1.46 लाख से अधिक नए इको क्लब स्थापित किए गए हैं।
शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत नियमों के निर्माण की स्थिति	शिक्षा का अधिकार नियम में संशोधन: संशोधन में 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए नियमित परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही, यदि कोई छात्र आगे की कक्षाओं में जाने संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करता है तो उसके लिए पुनः परीक्षा और अतिरिक्त निर्देश का प्रावधान भी किया गया है।
केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय खोलना	केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय का विस्तार: वंचित क्षेत्रों में छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार करने के लिए सरकार ने 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालयों को खोलने के लिए मंजूरी दी है।

PT 365

ENGLISH MEDIUM
9 JAN, 5 PM

हिन्दी माध्यम
17 JAN, 5 PM

📖 संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन

📖 अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।

📖 प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।

📖 लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।

1 वर्ष का करेंट अफेयर्स

प्रीलिम्स 2025 के लिए मात्र 60 घंटे में

11. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

विषय	प्रमुख पहलें/उपलब्धियां/उपाय
2024 में जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट	• घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 ○ यह राज्य एवं अखिल भारतीय स्तर पर मासिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोक्ता व्यय का अनुमान प्रदान करता है। ○ यह उपभोग पैटर्न, जीवन स्तर और घरेलू कल्याण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ○ कमोडिटी समूहों के लिए किए जाने वाले खर्च, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPIs) की तैयारी में सहायता करता है। ○ हालिया रिपोर्ट: दिसंबर 2024 में HCES 2023-24 रिपोर्ट जारी की गई। • असंगठित क्षेत्रक उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) ○ उद्देश्य: विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं (निर्माण को छोड़कर) में असंगठित गैर-कृषि उद्यमों का डेटा प्रदान करना। • आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) ○ जारी की गई रिपोर्ट्स: त्रैमासिक बुलेटिन (शहरी) और वार्षिक रिपोर्ट (ग्रामीण और शहरी)। ○ फोकस: श्रम बल भागीदारी दर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर। • उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) 2022-23 ○ उत्पादन, रोजगार और पूंजी निर्माण सहित विनिर्माण उद्योगों में उत्तार-चढ़ाव से सम्बंधित जानकारी। • व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (2022-23) ○ फोकस क्षेत्र: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल व्यय, ICT संबंधी कौशल, वित्तीय समावेशन, स्वच्छता और परिवहन की उपलब्धता।
GDP, CPI और IIP के आधार वर्ष में संशोधन	• GDP आधार वर्ष: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति (ACNAS) सके सुझाव पर 2022-23 को GDP के लिए आधार वर्ष के रूप में अपनाया गया। • गठित समितियां: नए डेटा स्रोतों, पद्धतिगत सुधारों और SNA 2025 को अपनाने पर फोकस करेंगी।
सामाजिक क्षेत्रक की सांख्यिकी पर प्रकाशन	• एनवीस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण सांख्यिकी: पर्यावरणीय संसाधनों, गुणवत्ता, आपदाओं और स्वास्थ्य संबंधी डेटा। • भारत में महिलाएं और पुरुष 2023: स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और निर्णय लेने के संबंध में लैंगिक रूप से अलग-अलग डेटा प्रदान करना। • एनवीस्टेट्स इंडिया 2024: पर्यावरण एकाउंट्स: SEEA फ्रेमवर्क के आधार पर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को जोड़ना। • सतत विकास लक्ष्य (SDG) रिपोर्ट: ○ राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2024। ○ सतत विकास लक्ष्यों पर डेटा श्लैपशॉट। ○ रिव्यू ऑफ माईलस्टोन सेटिंग फॉर SDGs।
डेटा गवर्नेंस संबंधी पहलें	• राष्ट्रीय मेटाडेटा संरचना (NMDS 2.0): इससे पारदर्शिता और डेटासेट संबंधी समझ में वृद्धि होती है। • विशिष्ट पहचानकर्ताओं का संकलन: डेटा प्लेटफॉर्म (जैसे, भविष्य और आधार) के बीच इंटरऑपरेबिलिटी।
MPLADS संबंधी अपडेट	• ई-साक्षी पोर्टल और मोबाइल ऐप: ○ यह सांसदों को कार्यों की सिफारिश करने और प्रगति की समीक्षा करने में सक्षम बनाता है। ○ यह हितधारकों (राज्यों, जिला प्राधिकरणों) के लिए कार्यक्षमता का विस्तार करता है।

12. परमाणु ऊर्जा विभाग (Department of Atomic Energy)

विषय	प्रमुख पहल/ उपलब्धियां /उपाय
परमाणु ऊर्जा का विस्तार	- देश का कुल यूरेनियम ऑक्साइड संसाधन 4,25,570 टन U3O8 तक पहुंच गया है। यूरेनियम अन्वेषण: भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खदान, जादूगोडा माइंस में नए भंडार की खोज की गई है, इससे खदान में संसाधन अगले पचास साल तक उपलब्ध रहेंगे। PHWR प्रगति: गुजरात के काकरापार में स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाले PHWR की पहली दो इकाइयों (KAPS-3 और 4) ने वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। - रावतभाटा परमाणु ऊर्जा परियोजना (RAPP) इकाई-7 ने प्रारंभिक ईंधन लोडिंग पूरी करते हुए पहली क्रिटिकैलिटी हासिल कर ली है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर: प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR 500 मेगावाट) ने सोडियम पंप कमीशनिंग सहित बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।
स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान	राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड: 362 केन्द्रों तक विस्तारित; दक्षिण-पूर्व एशिया में कैंसर नियंत्रण के लिए WHO के सहयोग से SEACan ग्रिड लॉन्च किया गया। चिकित्सा प्रगति: मधुमेह संबंधी पैर के घाव के उपचार के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड (NOx) रिलीज करने वाली ड्रेसिंग का विकास।
वैज्ञानिक अनुसंधान	MACE वेधशाला: कॉस्मिक किरणों के अध्ययन के लिए लद्दाख में एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। GRAPES-3 प्रयोग: यह कॉस्मिक-किरण प्रोटॉन स्पेक्ट्रम में अनसुलझी समस्या का पता लगाएगा, जो कॉस्मिक किरणों के प्रसार को समझने में मदद करेगा। टेराहर्ट्ज माइक्रोस्कोप: TIFR मुंबई परिसर में स्वदेशी रूप से एक नियर-फिल्ड स्कैनिंग टेराहर्ट्ज माइक्रोस्कोप विकसित किया गया है।
कृषि नवाचार	फसल विकास: दो नई उच्च उपज देने वाली और बहु रोग प्रतिरोधी उड़द की फसल किस्मों (ट्रॉम्बे जवाहर उड़द 339 (TJU-339) और ट्रॉम्बे जवाहर उड़द 130 (TJU-130)) को भारत सरकार द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए अधिसूचित किया गया है। BARC का योगदान: अब तक BARC द्वारा कुल 70 किस्में विकसित की गई हैं।
सुधार/ नीति	बंद ईंधन चक्र: परमाणु ऊर्जा में दीर्घकालिक स्थिरता के लिए बंद ईंधन चक्र पर निरंतर जोर दिया जा रहा है। WHO सहयोग: दक्षिण-पूर्व एशिया में कैंसर नियंत्रण के लिए NCG की सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की नीति शुरू की गई है। घरेलू संसाधन उपयोग: नियोडिमियम धातु निष्कर्षण जैसे स्वदेशी सामग्री के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

मासिक

समसामयिकी रिवीजन

कक्षाएं 2025

GS प्रीलिम्स और मेन्स

हिन्दी माध्यम

13. संचार मंत्रालय (Ministry of Communications)

13.1. डाक विभाग (Department of Posts)

विषय	प्रमुख पहल/ उपलब्धियां /उपाय
डाक कानून का आधुनिकीकरण	डाकघर अधिनियम, 2023: इसे 1898 के भारतीय डाकघर अधिनियम की जगह लाया गया है, नया कानून भारत के डाक फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाता है।
मेल और पार्सल डिलीवरी को बढ़ावा देना	पार्सल मॉनिटरिंग एप्लीकेशन (PMA): अकाउंटेबल आर्टिकल्स की वितरण क्षमता में 4.33 लाख से 5.35 करोड़ तक की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। लेटर बॉक्स का ई-क्लीयरेंस: पूरे भारत में 53,854 लेटर बॉक्स के लिए पारदर्शिता और ट्रैकिंग में वृद्धि हुई है। RFID तकनीक: मेल और पार्सल की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए 42 प्रमुख मेल एक्सचेंज हब पर RFID गेट लगाए गए हैं।
फिलैटली	राम जन्मभूमि मंदिर टिकट: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के स्मरण में इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। स्मारक टिकट: पेरिस ओलंपिक 2024, राजभाषा हीरक जयंती और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्ष जैसे आयोजनों के लिए जारी किए गए।
कुशल कार्यबल का निर्माण	iGOT कर्मयोगी पर प्रशिक्षण: 25 लाख पाठ्यक्रम पूरे करके महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई, जिससे नागरिक-केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को बढ़ावा मिला है।
वैश्विक पहुंच का विस्तार	डाकघर निर्यात केंद्र: MSMEs और ई-कॉमर्स के लिए निर्यात की सुविधा प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय सहयोग: 'भारत अफ्रीका पोस्टल लीडर मीट' और डाक भुगतान सेवा बहुपक्षीय समझौते में भागीदारी जैसी पहलें।
इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक	महिला सशक्तिकरण: 2.68 करोड़ नए खातों में से 59% खाते महिलाओं के हैं, जिनमें से 77 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं।

13.2. दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications: DOT)

विषय	प्रमुख पहल/ उपलब्धियां /उपाय
2024 में भारतीय दूरसंचार परिदृश्य	- दूरसंचार विभाग (DoT) भारतीय दूरसंचार पारितंत्र को सुधारने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिससे यह अधिक समावेशी, विकसित, त्वरित और सुरक्षित बन रहा है। - उपलब्धियां टेली घनत्व: यह 75.23% (मार्च 2014) से बढ़कर 84.49% (अक्टूबर 2024) हो गया है। - शहरी कनेक्शन में 19.11% की वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण कनेक्शन में 39.58% की वृद्धि हुई। इंटरनेट कनेक्शन: मार्च, 2014 के 25.15 करोड़ से बढ़कर जून, 2024 में 96.96 करोड़ हो गए, जो 285.53% की वृद्धि को दर्शाता है। ब्रॉडबैंड वृद्धि: मार्च, 2014 के 6.1 करोड़ से बढ़कर अगस्त, 2024 में 94.92 हो गए, जो 1452% की वृद्धि को दर्शाता है। डेटा खपत: प्रति वायरलेस औसत मासिक डेटा खपत मार्च, 2014 के 61.66 MB से 353 गुना बढ़कर जून, 2024 में 21.30 GB हो गई। डेटा की लागत: वायरलेस डेटा की प्रति GB लागत में 96.91% की महत्वपूर्ण कमी आई है, जो दिसंबर 2014 के 268.97 रुपये से घटकर जून 2024 में 8.31 रुपये हो गई है। टेलीकॉम क्षेत्रक में FDI: 2024-25 (अप्रैल से सितंबर) में यह 670 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2023-24 में यह 282 मिलियन अमेरिकी डॉलर था।

दूरसंचार सुधार	• दूरसंचार अधिनियम, 2023: ○ यह औपनिवेशिक युग के कानूनों को प्रतिस्थापित करता है और एक आधुनिक नियामक फ्रेमवर्क को लागू करता है। ○ इस अधिनियम में स्पेक्ट्रम आवंटन, नियामक सैंडबॉक्स, नवाचार प्रोत्साहन, राष्ट्रीय सुरक्षा और उपयोगकर्ता सुरक्षा के प्रावधान शामिल हैं। • साइबर-अपराधों को रोकने के लिए सुधार: ○ संचार साथी पोर्टल: यह संदिग्ध कॉल, धोखाधड़ी, खोए/चोरी हुए हैंडसेट की रिपोर्टिंग के लिए एक पोर्टल है साथ ही यह सेकेंड-हैंड मोबाइल उपकरणों का सत्यापन करता है। ○ डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP): यह एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जो दूरसंचार हितधारकों, बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ी जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। ○ ASTR AI टूल: यह नकली दस्तावेजों की मदद से लिए गए मोबाइल कनेक्शन्स की पहचान करने में मदद करता है और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकता है। ○ अंतर्राष्ट्रीय इनकर्मिंग स्पूफ़ कॉलस रोकथाम प्रणाली: यह स्पूफ कॉल की पहचान करती है और उन्हें ब्लॉक करती है। • राइट ऑफ वे (RoW) और गति शक्ति संचार पोर्टल: ○ गतिशक्ति संचार पोर्टल RoW आवेदनों के कुशल प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे अनुमोदन में लगने वाला समय 2019 के 448 दिनों से घटकर 2024 में लगभग 60 दिन हो गया है। ○ राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP): DoT ने योजना को अधिक प्रभावी बनाने और ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में 4G की उपलब्धता का विस्तार करने के लिए 13 लाख किलोमीटर रूट से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) की मैपिंग की गई है। • अनुपालन संबंधी बोझ को कम करना: ○ 114 में से 109 अनुपालन आवश्यकताओं को समाप्त किया गया है, दूरसंचार लाइसेंस के लिए पंजीकरण जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, साथ ही सरल संचार पोर्टल की शुरुआत की गई है। ○ 100, 101, 102 और 108 जैसे कई आपातकालीन नंबरों को एकीकृत करने के लिए एक एकल आपातकालीन नंबर 112 शुरू किया गया है। • आपदा प्रबंधन ○ सेल ब्रॉडकास्टिंग (CB) प्रणाली: यह एक आपातकालीन चेतावनी प्रणाली है, जो आपात स्थिति के दौरान लक्षित क्षेत्र में अलर्ट जारी करने के लिए भारत के 80% दूरसंचार नेटवर्क को कवर करती है।
5G और 6G	• 5G सेवाओं की शुरुआत ○ 5G कवरेज: 31 अक्टूबर 2024 तक, देश के 783 जिलों में से 779 जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध थीं। ○ सरकारी पहलें: ▪ नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम का आवंटन। ▪ तर्कसंगत AGR और BGs जैसे वित्तीय सुधार। ▪ RoW अनुमतियों का सरलीकरण और दूरसंचार अवसंरचना का विकास। ▪ छोटे सेल स्थापित करने के लिए स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग। • 100 5G लैब्स पहल का कार्यान्वयन ○ 5G-संबंधित कौशल, UG/ PG परियोजनाओं और शिक्षा-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किया गया है। ○ लक्ष्य: स्टार्टअप और MSMEs का सहयोग करना और 6G जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए तैयारी करना। • भारत 6G विजन और भारत 6G अलायंस (B6GA) ○ उद्देश्य: 2030 तक भारत को 6G तकनीक में अग्रणी के रूप में स्थापित करना। ○ सहयोग: वैश्विक निकायों (जैसे, NGMN अलायंस, 6G फोरम और ATIS USA) के साथ साझेदारी। ○ फोकस क्षेत्र: स्पेक्ट्रम, डिवाइस प्रौद्योगिकियां, स्थिरता, AI, सेंसिंग और सुरक्षा।
परियोजनाएं और पहलें	• डिजिटल भारत निधि (DBN) ○ पूर्ववर्ती नाम: यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ○ उद्देश्य: दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करना।

	○ भारतनेट: 6.92 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई; 2.14 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) को इस सेवा से जोड़ा गया। ○ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक विकास: ▪ वंचित गांवों में 1,358 साइटें स्थापित। ▪ अरुणाचल प्रदेश और असम में 660 टावर स्थापित। ○ द्वीप कनेक्टिविटी: ▪ अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में सबमरीन OFC परियोजना, लक्षद्वीप में 5G और FTTH सेवाएं शुरू की गईं। ● व्यापक दूरसंचार विकास योजनाएं ○ अछूते गांव: सीमावर्ती और वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित क्षेत्रों में 4G सेवाएं प्रदान करने वाली परियोजनाएं शुरू की गईं। ○ आकांक्षी जिले: 7,287 गांवों को लक्षित किया गया; 3,638 गांवों को कवर करने वाली 2,387 साइटें चालू की गईं। ● दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) ○ उद्देश्य: ग्रामीण संचार प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान एवं विकास को वित्त पोषण प्रदान करना और स्वदेशी समाधानों को बढ़ावा देना। ● उत्पादन लिंक प्रोत्साहन (PLI) योजना: ○ प्रभाव: घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिला; वित्तीय वर्ष 2023-24 में दूरसंचार उत्पादों की बिक्री 2019-20 के मुकाबले 500% बढ़ी।
महत्वपूर्ण घटनाएं	● विश्व दूरसंचार मानकीकरण संगठन (WTSA) ○ आयोजन: 14 से 24 अक्टूबर, 2024 तक नई दिल्ली में। ○ भारत के प्रस्ताव: ▪ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI प्रौद्योगिकियों, मेटावर्स और वाहन संचार के लिए मानकीकरण गतिविधियों को बढ़ावा देना। ▪ स्थिरता, पहुंच और साइबर सुरक्षा मानक।
वैश्विक सूचकांकों में भारत की रैंकिंग	● नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स (NRI) 2024: देश ने 60वें स्थान से 49वें स्थान पर पहुंचकर महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, जो देश में बेहतर डिजिटल नीतियों को दर्शाता है। ● वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024: भारत ने 98.49/ 100 के स्कोर के साथ टियर 1 का दर्जा हासिल किया है, जो साइबर सुरक्षा के मामले में भारत के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

दिव्यक रिवीजन क्लासेस

GS प्रीलिम्स

UPSC CSE 2025

11 फरवरी, दोपहर 1 बजे

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

14. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law and Justice)

प्रमुख उपलब्धियाँ	- एक साथ चुनाव पर रिपोर्ट: श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति ने दो-स्तरीय प्रक्रिया की सिफारिश की है। इसमें लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनावों को एक साथ करवाने का प्रस्ताव है। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव आयोजित हों, जिसमें सभी स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची का प्रयोग किया जाना चाहिए। - नए आपराधिक कानून लागू: तीन नए कानून - भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के सदी पुराने कानूनों को प्रतिस्थापित करेंगे। 22वें विधि आयोग की सिफारिशें: आयोग ने विभिन्न मुद्दों पर सिफारिशें की हैं, जिनमें प्रमुख हैं: - NRIs और OCIs को विवाह करने में आने वाली समस्याओं के लिए व्यापक कानून का निर्माण। - आपराधिक मानहानि का संरक्षण, प्रतिष्ठा के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन। - महामारी रोग अधिनियम, 1897 की समीक्षा, इसके संशोधन या भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए नए कानून की सिफारिश।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:	- कानून और विवाद समाधान पर भारत-सिंगापुर समझौता ज्ञापन (MoU): वैकल्पिक विवाद समाधान और अंतर्राष्ट्रीय विवाद समाधान में सहयोग हेतु समझौता। - ब्रिक्स न्याय मंत्रियों की बैठक: भारत ने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के जरिए न्यायिक बोझ को कम करने में अपने कानूनी सुधारों और मध्यस्थता अधिनियम की भूमिका को रेखांकित किया है। - भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ब्रिटेन दौरा: इसमें कानूनों को सरल बनाने, ADR के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और ब्रिटिश कानूनी पेशेवरों को भारत में काम करने की अनुमति देने पर चर्चा की गई। - कानूनी सहयोग संधियाँ: भारत ने वियतनाम के साथ एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को अंतिम रूप दिया और हेग कन्वेंशन के तहत न्यायिक दस्तावेज सेवा से जुड़े 3829 अनुरोधों पर कार्यवाही की।
डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा:	- लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और ब्रीफिंग सिस्टम (LIMBS) की शुरुआत: यह भारत सरकार से जुड़े अदालती मामलों को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। - विभाग ने कागज रहित कार्यालय की ओर कदम बढ़ाया, जिसके तहत कई दस्तावेजों और प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया गया। - विधिक मामलों के विभाग ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत की: - साइबर सुरक्षा संकट प्रबंधन योजना (CCMP) के प्रारंभिक चरण को लागू किया गया। - विभाग द्वारा साइबर सुरक्षा पर मासिक ऑनलाइन बुलेटिन भी शुरू किया गया, जिससे साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके।

CSAT

क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2025

(इसका उद्देश्य मूलभूत अवधारणाओं को रिवाइज करना और उन्हें सुदृढ़ करना, समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ाना, वेश्लेषणात्मक कौशल को बेहतर बनाना, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए समझ कौशल में सुधार करना है।)

प्रारंभ

English Medium

21 January, 1 PM

प्रारंभ

हिन्दी माध्यम

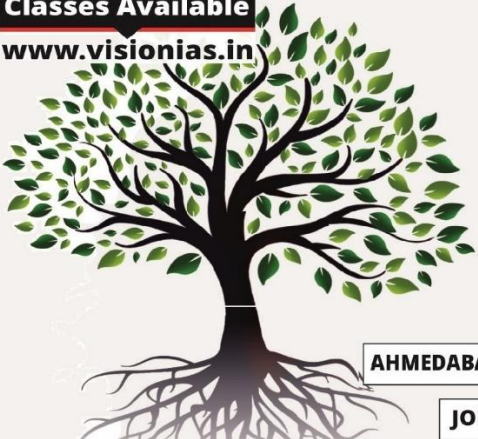
30 January, 1 PM

(Offline/Online)

15. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

विद्युत की मांग और खपत	- भारत में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 250 GW की अब तक की सर्वाधिक विद्युत मांग को पूरा किया गया है। - प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत में 45.8% की वृद्धि हुई है। यह खपत 2023-24 में 1,395 kWh तक पहुंच गई, जबकि 2013-14 में यह 957 kWh थी।
सार्वभौमिक विद्युतीकरण	- भारत ने सार्वभौमिक विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। - ग्रामीण क्षेत्रों में औसत विद्युत उपलब्धता 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर 2024 में 21.9 घंटे हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 23.4 घंटे तक पहुंच गई है।
उपभोक्ता अधिकार	2024 में नए उपभोक्ता अधिकार नियम लागू किए गए। इससे रूफटॉप सौर ऊर्जा के लिए पैनेल लगाने और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जैसी प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं। साथ ही बिलिंग और नए कनेक्शन से संबंधित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया गया है।
नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार	2014 के बाद से भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 129 GW की बढ़ोतरी हुई है। इसमें 91 GW सौर ऊर्जा और 27 GW पवन ऊर्जा शामिल है।
ऊर्जा दक्षता और संधारणीयता	EV चार्जिंग दिशा-निर्देश 2024: इसे पूरे देश में EV चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करने के लिए जारी किया गया है। इसके तहत 2030 तक चार्जर पॉइंट्स की संख्या को 34,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सौर ऊर्जा उपयोग और EV की बढ़ती मांग के अनुरूप ग्रिड को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सतत भवन कोड: व्यावसायिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण और सतत भवन कोड (ECSBC) तथा आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता (ENS) की शुरुआत की गई है। साथ ही बड़े वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों के लिए बिजली की खपत को 18% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत का कार्बन बाजार: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना शुरू की गई है। अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य क्षेत्रों में ट्रेडिंग और अप्रैल 2024 तक स्वैच्छिक क्षेत्रों में ट्रेडिंग शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। उजाला कार्यक्रम: इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत 36.87 करोड़ LED बल्ब, 72.18 लाख LED ठूब लाइट और 23.59 लाख ऊर्जा-कुशल पंखे वितरित किए गए। इससे ऊर्जा की बचत, कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, और उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया गया। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP): इसे 2015 में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को LED से बदलने के लिए लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी और देश भर की नगरपालिकाओं के लिए वित्तीय बचत सुनिश्चित करता है।
साइबर सुरक्षा	कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल-पावर (CSIRT - पावर) सुविधा की शुरुआत की गई। यह साइबर खतरों के खिलाफ इस क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा।

LIVE/ONLINE
Classes Available
www.visionias.in



Foundation Course

GENERAL STUDIES

PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

DELHI: 21 JAN, 1 PM | 31 JAN, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 6 JAN, 8 AM

हिन्दी माध्यम DELHI: 4 फरवरी, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN

BENGALURU: 18 FEB

BHOPAL: 5 DEC

HYDERABAD: 12 FEB

JAIPUR: 20 JAN

JODHPUR: 3 DEC

LUCKNOW: 11 FEB

PUNE: 20 JAN

ADMISSION OPEN

CHANDIGARH

16. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New & Renewable Energy)

नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विस्तार	कुल स्थापित क्षमता: नवंबर 2024 में भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 214 GW तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में स्थापित 187.05 GW क्षमता की तुलना में 14% अधिक है। क्षमता में वृद्धि: अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच लगभग 15 GW नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में जोड़ी गई 7.57 GW क्षमता के लगभग दोगुनी है।
सौर और पवन ऊर्जा का विकास	सौर ऊर्जा: 2024 में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 94.17 GW तक पहुंच गई। इससे सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में दुनिया भर में भारत की स्थिति मजबूत हुई। पवन ऊर्जा: पवन ऊर्जा क्षमता 47.96 GW तक पहुंच गई है। इसने कुल नवीकरणीय ऊर्जा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रधान मंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGMY)	शुभारंभ और उद्देश्य: इसे 13 फरवरी 2024 को 75,021 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया। इस योजना का उद्देश्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित करना और प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करना है। प्रगति: दस महीनों के भीतर 7 लाख इंस्टॉलेशन पूरे किए गए हैं। प्रति माह औसतन 70,000 इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं - जो पिछले औसत 7,000 इंस्टॉलेशन से दस गुना अधिक है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने असाधारण प्रगति दिखाई है।
वैश्विक सहभागिता और आयोजन	चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी (RE-INVEST): इसे 16-18 सितंबर को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया। इसमें भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया और वैश्विक हितधारकों को आकर्षित करने पर जोर दिया गया। ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICGH): इसे 11-13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में प्रगति के महत्व और इस क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित किया गया।

17. खान मंत्रालय (Ministry of Mines)

विषय	प्रमुख पहल/ उपलब्धियां/ उपाय
नीतिगत पहल	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम और नियमों में संशोधन - MMDR अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में बेरिलियम, कोबाल्ट, टंगस्टन सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए संशोधन किया गया। - MMDR अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नए नियमों में शामिल हैं: खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत संशोधन नियम, 2024: लघु खनिकों के लिए दंड को सुव्यवस्थित किया गया और खनिजों के सीमा मूल्य से नीचे के निपटान के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए। खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2024: स्टार रेटिंग के लिए खनन योजना प्रस्तुत करने और स्व-मूल्यांकन में लचीलापन लाया गया। खनिज (नीलासी) संशोधन नियम, 2024: MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 के अंतर्गत अन्वेषण लाइसेंस प्रावधानों को शामिल किया गया। परमाणु खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2024: MMDR संशोधन अधिनियम, 2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। खनिज (परमाणु और हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2024: महत्वपूर्ण खनिजों के औसत बिक्री मूल्य की गणना के लिए कार्यप्रणाली निर्दिष्ट की गई। अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम और नियम में संशोधन - निर्माण में प्रयुक्त होने वाली रेत और पॉलिमेटेलिक नोड्यूल जैसे अपतटीय खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों को युक्तिसंगत बनाया गया।

मील के पत्थर और मान्यता	- अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला (IITF) 2024: - मंत्रालय के मंडप को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान (स्वर्ण) मिला। इसका थीम 'खनिज से मील के पत्थर' था। - जिला खनिज फाउंडेशन (DMF): - संशोधित PMKKKY दिशानिर्देशों ने उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के उपयोग को 70% तक बढ़ा दिया। - पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय DMF पोर्टल शुरू किया गया।
महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए उठाए गए कदम (वित्त वर्ष 2024-25)	- अन्वेषण परियोजनाएं: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए 195 खनिज अन्वेषण परियोजनाएं शुरू कीं। - नीलामी अधिकारिता: मंत्रालय को MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 20A के अंतर्गत अन्वेषण लाइसेंसों की नीलामी करने का अधिकार दिया गया है। - निजी भागीदारी: राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) द्वारा 28 निजी अन्वेषण एजेंसियों को अधिसूचित और वित्तपोषित किया गया है। - महत्वपूर्ण खनिज मिशन: घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेशी अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में इसकी घोषणा की गई।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और पैनल	- क्रिटिकल ट्रांजिशन खनिजों पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का पैनल में भाग लेकर ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक समानता में योगदान दिया। - इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) पर चर्चा में भाग लिया, जिसमें खनिज संसाधनों के मानचित्रण और संधारणीयता संबंधी मानकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)	- कानूनी सशक्तिकरण - खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (MMDR) की धारा 9B राज्य सरकारों को खनन कार्यों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) स्थापित करने का अधिकार देती है। राज्य सरकारों को DMFs की संरचना और कार्यों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। - प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY): MMDR अधिनियम की धारा 20A के तहत, केंद्र सरकार ने PMKKKY दिशानिर्देश जारी किए। साथ ही राज्य सरकारों को इन दिशानिर्देशों को अपने DMF नियमों में शामिल करने का निर्देश दिया।
महत्वपूर्ण खनिज मिशन	- इस मिशन की घोषणा: - वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा की गई। - उद्देश्य: महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्तियों के घरेलू उत्पादन, पुनर्चक्रण और विदेशी अधिग्रहण को मजबूत करना। इस मिशन में शामिल हैं: - प्रौद्योगिकी विकास - कुशल कार्यबल प्रशिक्षण - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) ढांचा - उपयुक्त वित्तपोषण तंत्र - प्रमुख लक्ष्य: - भारत में एक टिकाऊ, लचीली और आत्मनिर्भर महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला विकसित करना। - अन्वेषण, निष्कर्षण और प्रसंस्करण से लेकर अंतिम उपयोग, पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करना।
खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)	- खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP) संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली एक बहुपक्षीय पहल है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना और चीन पर निर्भरता कम करना है। - भारत की भागीदारी: - भारत MSP का 14वां सदस्य देश बना। - इसमें शामिल होकर भारत ने MSP द्वारा रेखांकित पर्यावरण संबंधी, सामाजिक और प्रशासनिक (ESG) मानकों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET)	- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) की स्थापना भारत सरकार द्वारा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत की गई थी। - उद्देश्य: खनिज संसाधन मानचित्रण और खोज को बढ़ाने हेतु देश भर में क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ावा देना।
अन्य पहल	- खानों की स्टार रेटिंग: भारतीय खान ब्यूरो ने छोटी और बड़ी खानों के लिए अलग-अलग टेम्पलेट पेश करते हुए एक नई ऑनलाइन स्टार रेटिंग प्रणाली शुरू की। - खनन निगरानी प्रणाली (MSS): IBM की उपग्रह आधारित प्रणाली MSS ने 2022-23 के दौरान अनधिकृत खनन के 7 मामलों का पता लगाया। - S&T-PRISM 2.0 योजना: इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स/MSMEs को वित्त पोषण प्रदान करके खनन और धातुशोधन क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देना है, ताकि वे निवेश आकर्षित करने या ऋण प्राप्त करने के स्तर तक पहुंच सकें।

DAKSHA MAINS
 MENTORING PROGRAM 2024

दक्ष : मुख्य परीक्षा 2025 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम

(मुख्य परीक्षा 2025 के लिए स्ट्रेटैजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)

दिनांक
13 जनवरी

अवधि
3 महीने

हिन्दी/English माध्यम

कार्यक्रम की विशेषताएं

अत्यधिक अनुमति और योग्य मेंटर्स की टीम

अधिकतम अंक दिलाने और प्रदर्शन में सुधार पर विशेष बल

'दक्ष' मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा

मेंटर के साथ वन-टू-वन सेशन

मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन, निबंध और नीतिशास्त्र विषयों के लिए रिवीजन एवं प्रैक्टिस की बेहतर व्यवस्था

शोध आधारित और विषय के अनुसार रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स

रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप-सेशन

अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन, निगरानी और आवश्यक सुधार के लिए सुझाव

For any assistance call us at:
+91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in

18. आयुष मंत्रालय (Ministry of Ayush)

विषय	प्रमुख पहल/ उपलब्धियां/ उपाय
पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक मान्यता	- WHO द्वारा ICD-11 में पारंपरिक चिकित्सा के लिए अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण (ICD) की शुरूआत: आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा में रोगों को परिभाषित करने वाली शब्दावली को WHO के ICD-11 में शामिल किया गया। इससे स्वास्थ्य देखभाल, बीमा और नीति-निर्माण में सुधार होगा। - अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति: वियतनाम, मलेशिया और जिम्बाब्वे के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर करके वैश्विक सहयोग को मजबूत किया गया। - WHO पारंपरिक चिकित्सा केंद्र: भारत ने पारंपरिक और एकीकृत चिकित्सा का समर्थन करने के लिए गुजरात में WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र को 85 मिलियन डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई।
बुनियादी ढांचे का विकास	- अनुसंधान सुविधाएं: - हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (CRIYN) का उद्घाटन किया गया। - दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIA) के चरण II में पंचकर्म अस्पताल और आयुर्वेद फार्मसी को शामिल किया गया है। - आयुष कल्याण केंद्र: भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित प्रमुख स्थानों पर आयुष कल्याण केंद्रों की स्थापना करना। - योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान: ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इन संस्थानों की आधारशिला रखी गई है।
अनुसंधान और विकास	- उन्नत अनुसंधान केंद्र: - एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए चार एम्स में छह आयुष-ICMR केंद्रों का शुभारंभ किया। - मधुमेह, संपोषणीयता और आयुर्वेदिक वनस्पति अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने वाले उत्कृष्टता केंद्र। - समझौता ज्ञापन: किशोर पोषण सुधार के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग।
अभिनव परियोजनाएं	- आयुष मंडप: - आयुष मंत्रालय के मंडप ने आयुर्वेद से प्रेरित खेलों और प्रदर्शनियों के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF)-2024 में रजत पदक जीता। - आयुष औषधि केंद्र: गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक दवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए पहली फार्मसी का उद्घाटन किया गया।
आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देना	10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) का विषय 'स्वयं और समाज के लिए योग' था। इस अवसर पर विश्व स्तर पर 24 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। 9वें आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। - पूरे देश से भागीदारी के साथ 7वां प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। - गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक दवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए आयुष औषधि केंद्र शुरू किया गया।

19. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

विषय	प्रमुख पहल/ उपलब्धियां/ उपाय
प्रमुख योजनाएं और पहल	- ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना - उद्देश्य: उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना। - बजट: 25,938 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक)। - हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और विनिर्माण (FAME-II) योजना - उद्देश्य: भारत में विद्युत गतिशीलता को बढ़ावा देना। - बजट: 11,500 करोड़ रुपये (2019 में लॉन्च की गई)।

- **PM ई-ड्राइव योजना**
 - उद्देश्य: हरित गतिशीलता और EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास।
 - बजट: 10,900 करोड़ रुपये (अक्टूबर 2024 - मार्च 2026)।
- **इलेक्ट्रिक यात्री कारों के लिए योजना (SMEC)**
 - उद्देश्य: वैश्विक निवेश आकर्षित करना और EV विनिर्माण को बढ़ावा देना।
- **उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण के लिए PLI योजना**
 - बजट: 7 वर्षों के लिए 18,100 करोड़ रुपये।

फास्ट ट्रेक कोर्स 2025

सामान्य अध्ययन प्रीलिम्स



इस कोर्स का उद्देश्य

GS प्रीलिम्स कोर्स विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए तैयार किया गया है जो GS पेपर I की तैयारी में अपने स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं। इसमें GS पेपर I प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस, विगत वर्षों के UPSC पेपर का विश्लेषण और Vision IAS के क्लासरूम टेस्ट की प्रैक्टिस एवं चर्चा शामिल होगी। हमारा लक्ष्य है कि अभ्यर्थी बेहतर परफॉर्म करें और कोर्स पूरा करने के बाद अपने प्रीलिम्स स्कोर में एक बड़ा सुधार करें।



इसमें निम्नलिखित शामिल है:



पर्सनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस तक पहुंच



प्रीलिम्स सिलेबस के लिए विस्तृत, प्रासंगिक और अपडेटेड स्टडी मटेरियल की साफ्ट कॉपी



PT 365 की कक्षाएं



सेक्शनल मिनी टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव करेंट अफेयर्स



प्रवेश प्रारंभ

Available in English & हिन्दी

Live/Online
Classes available

20. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

मंत्रालय की योजनाओं, उपलब्धियों और पहलों की प्रमुख विशेषताएं	- जनजातीय सशक्तिकरण और प्रगति के लिए बजट: मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। यह 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 13,000 करोड़ रुपये हो गया है। - धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ: लगभग 63,843 जनजातीय गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास में गंभीर अंतराल को दूर करने के लिए। - प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM-JANMAN): 15 जनवरी को प्रधान मंत्री ने 4450 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। - प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (PMJVM): इस योजना के तहत पांच वर्षों के लिए 1612 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। - MFPs योजना के लिए MSP के अंतर्गत कवर किए जाने वाले MFPs की अधिसूचित वस्तुओं की सूची में 87 लघु वनोपज (MFPs) को जोड़ा गया। - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS): प्रधान मंत्री ने 40 EMRS का उद्घाटन किया तथा 25 और EMRS की आधारशिला रखी। इन EMRS पर 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होगा। अब तक 728 EMRS को मंजूरी दी जा चुकी है। - माननीय प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक एक वर्ष जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। - केंद्रीय बजट 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई है।
जनजातीय सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति	- भारत सरकार जनजातियों के लिए 5 छात्रवृत्ति योजनाएं लागू करती है। इसके तहत 2500 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट से हर साल 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें शामिल हैं: - प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं - अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति - अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप - अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। (शीर्ष श्रेणी के संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए) - अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (विदेश में उच्चतर अध्ययन के लिए)
वन अधिकार अधिनियम	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत कुल 23.73 लाख व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार और कुल 1.16 लाख सामुदायिक स्वामित्व अधिकार वितरित किए गए हैं। इसके तहत लगभग 190.39 लाख एकड़ भूमि वितरित की गई है।

पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम

सिविल सेवा परीक्षा 2024

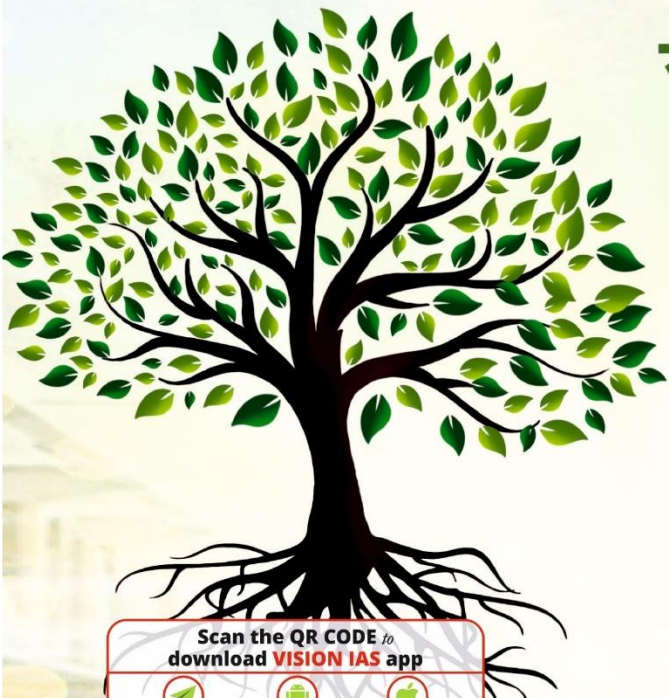
प्रवेश प्रारंभ

अधिक जानकारी और रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें

हिंदी और अंग्रेजी माध्यम

21. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)

आयोजित प्रमुख त्यौहार/ कार्यक्रम	46वां विश्व धरोहर समिति सत्र: इसे दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें 140 से अधिक देशों के 2900 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। - प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन: बौद्ध सिद्धांतों पर केंद्रित यह सम्मेलन नवंबर में आयोजित किया गया। - अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस: 1500 प्रतिनिधियों के साथ मनाया गया। - भारतीय कला महोत्सव: क्षेत्रीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला उत्तर पूर्व क्षेत्र का कार्यक्रम। - आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम: वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव, भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव और मीरा महोत्सव सहित कई कार्यक्रम पूरे भारत में आयोजित किए गए। - अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो: कोलकाता में आयोजित किया गया जिसमें चर्चाएं और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
प्रमुख पहल	- प्रोजेक्ट परी: भारतीय लोक कला पहल, जिसमें 200 से अधिक कलाकारों और 300 छात्रों ने भाग लिया। - संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सांस्कृतिक संपत्ति समझौता: प्राचीन कलाकृतियों की तस्करी को रोकने के लिए हस्ताक्षर किये गये। - युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय: नई दिल्ली में निर्माणाधीन विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय। - UCL और BSIP के साथ AnSI समझौता ज्ञापन: जैव पुरातत्व और जीनोमिक्स में अध्ययन को बढ़ावा देना। - नवीन शास्त्रीय भाषाएँ: असमिया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली को मान्यता दी गई। - हर घर तिरंगा अभियान: 5 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिससे राष्ट्रीय गौरव बढ़ा। - असम से भारत का नामांकन; "मोइदुल्लाह: अहोम राजवंश की टीलेनुमा संरचना में दफनाने की प्रणाली" को जुलाई, 2024 में सांस्कृतिक विरासत के रूप में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।



फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2026

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

Scan the QR CODE to download VISION IAS app



- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

DELHI: 4 फरवरी, 11 AM

JAIPUR: 20 जनवरी

JODHPUR: 3 दिसंबर

प्रवेश प्रारम्भ

BHOPAL | LUCKNOW

22. संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs)

वर्ष 2024 में संसद के दोनों सदन द्वारा पारित विधेयक	- कुछ महत्वपूर्ण कानूनों के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं: - जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधन करता है, ताकि मामूली उल्लंघन के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को अपराध से मुक्त किया जा सके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। - सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024, सार्वजनिक परीक्षा प्रणालियों में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने का आश्वासन देता है। - जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2024, अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण प्रदान करना और इन अधिनियमों के कुछ प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुरूप बनाना। - संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024: जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जातियों की सूची में क्रम संख्या 5 पर चूड़ा, भंगी, वाल्मीकि, मेहतर के पर्यायवाची के रूप में वाल्मीकि समुदाय को शामिल करने के लिए। - संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2024: जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए। - भारतीय वायुयान विधेयक, 2024: समय-समय पर वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधनों द्वारा किए गए सम्मिलन/चूक/विलोपन के कारण उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने के लिए वायुयान अधिनियम को पुनः अधिनियमित करने हेतु।
विशेष कार्यक्रम	शीतकालीन सत्र 2024: चर्चाओं और स्मृति कार्यक्रमों के साथ संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई।
नई पहलों का शुभारंभ: सरकार के 100 दिन के एजेंडे के अंतर्गत	निम्नलिखित छह पहलों का शुभारंभ किया गया: - - राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) 2.0 - NeVA 2.0 मोबाइल ऐप - राष्ट्रीय युवा संसद योजना (NYPS) 2.0 - एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता - अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली समिति (CSLMS) - सलाहकार समिति प्रबंधन प्रणाली (CCMS)
युवा संसद हेतु पहलें	- प्रतियोगिताएं और प्रशिक्षण: - स्कूलों, कॉलेजों और केंद्रीय विद्यालयों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम। - युवा संसद की बैठकें आयोजित करने के लिए मध्य प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। - नई पहलें: - EMRS के जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता शुरू की गई।
हिंदी का प्रचार-प्रसार	- विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। - भारत के संविधान का संस्कृत और मैथिली संस्करण जारी किया गया।

23. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (Department of Administrative Reforms and Public Grievances)

100-दिवसीय कार्य योजना का क्रियान्वयन	94 संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों में ई-ऑफिस प्रणालियां शुरू की गईं। - लोक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशा-निर्देश 2024 में जारी किए गए। - लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 की योजना का नवीनीकरण किया गया। - प्रशासनिक सुधारों और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने हेतु गाम्बिया, मालदीव और मलेशिया के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
---------------------------------------	--

27वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन	3-4 सितंबर 2024 को मुंबई में आयोजित किया गया, जिसका विषय था "विकसित भारत: सुरक्षित और सतत ई-सेवा वितरण।" - ई-गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए सोलह राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए, जो डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। - मुंबई घोषणा-पत्र को अपनाया गया, जो 2047 के लिए भारत के दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जिसमें आईटी क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, सुदृढ़ शिकायत निवारण और उन्नत साइबर सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया है।
लोक शिकायत निवारण	- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) को अप्रैल 2024 में कॉमनवेल्थ देशों के सम्मेलन में "स्टेट-ऑफ-द-आर्ट शिकायत निवारण प्रणाली" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 2024 में CPGRAMS पोर्टल पर 24 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 98 प्रतिशत का 12 दिनों के औसत निपटान समय के भीतर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। - शिकायत निवारण आकलन एवं सूचकांक (GRAI) 2023 ने महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया, GRAI 2022 की तुलना में 89 मंत्रालयों और विभागों में से 85 ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान की दर में सुधार किया।
विशेष अभियान और पहलें	- सरकारी विभागों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और विभागों में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 4.0 शुरू किया गया। - जमीनी स्तर पर सुशासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए चतुर्थ सुशासन सप्ताह और प्रशासन गांव की ओर अभियान 2024 आयोजित किया गया। - राज्यों के बीच ज्ञान साझा करने को बढ़ावा देने के लिए गुवाहाटी और रायपुर में सुशासन प्रथाओं के अनुकरण के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए।
सहयोग और मान्यताएं	- महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों और सात राज्यों के सर्विस कमीशन के साथ सहयोग स्थापित किया गया, ताकि सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा दिया जा सके। - सार्वजनिक नीति और शासन में श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया और सिंगापुर के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग किया गया। - राजभाषा को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए, DARPG को वर्ष 2023-24 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) से सम्मानित किया गया।

"You are as strong as your Foundation"

FOUNDATION COURSE

GENERAL STUDIES

PRELIMS CUM MAINS

2026, 2027 & 2028

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 21 JAN, 1 PM | 31 JAN, 5 PM

GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 6 JAN, 8 AM

हिन्दी माध्यम DELHI: 4 फरवरी, 11 AM

AHMEDABAD: 4 JAN | BENGALURU: 18 FEB | BHOPAL: 5 DEC | HYDERABAD: 12 FEB | JAIPUR: 20 JAN

JODHPUR: 3 DEC | LUCKNOW: 11 FEB | PUNE: 20 JAN | ADMISSION OPEN | CHANDIGARH

24. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textiles)

कपास क्षेत्र	MSP खरीद: भारतीय कपास निगम (CCI) ने अक्टूबर 2024 में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) खरीद अभियान शुरू किया, जिसमें दिसंबर 2024 तक लगभग 42.11 लाख गांठों की खरीद की गई। इससे देश भर के लगभग 7.75 लाख कपास किसानों को लाभ हुआ। कस्तूरी कॉटन इंडिया: प्रीमियम गुणवत्ता वाले भारतीय कपास को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के लिए, "कस्तूरी कॉटन इंडिया" ब्रांड को ट्रेडमार्क के रूप में पंजीकृत किया गया है। - इस पहल का उद्देश्य जिम्मेदार सोर्सिंग को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के लिए आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता को बढ़ाना है।
ऊन क्षेत्र	एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (IWDP): मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए 126 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय आवंटन के साथ IWDP तैयार किया है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड को प्रमुख ऊन उत्पादक राज्यों में इसके कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।
रेशम क्षेत्र	कच्चे रेशम का उत्पादन: इस वर्ष कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़कर 38,913 मीट्रिक टन हो गया है, जो इस क्षेत्रक में विकास को दर्शाता है।
अवसंरचना विकास	PM MITRA पार्क: सरकार ने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और अपैरल (PM MITRA) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है, जो ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड साइट्स पर बनाए जाएंगे। - इन पार्कों में सात वर्षों में 2027-28 तक 4,445 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्लग-एंड-प्ले सुविधाओं सहित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा होगा। वाराणसी में निफ्ट परिसर: फैशन प्रौद्योगिकी में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फरवरी 2024 में वाराणसी में 19वें राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) परिसर की आधारशिला रखी गई।
कारीगर संगठित करना	पहचान पहल: वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय द्वारा "पहचान" पहल के तहत कुल 32.03 लाख कारीगरों को संगठित किया गया है, जिनमें से 9.56 लाख पुरुष कारीगर और 20 लाख महिला कारीगर हैं।
वस्त्र व्यापार संवर्धन (TTP)	समर्थ: सरकार ने समर्थ योजना की कार्यान्वयन अवधि को 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए 495 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट (RoSCTL): सरकार ने राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों पर छूट (RoSCTL) योजना को मंजूरी दी है, जो वस्त्र, परिधान और मेकअप के निर्यात पर अंतर्निहित करों/ शुल्कों को छूट प्रदान करेगी, ताकि इन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। भारत टेक्स 2025: यह वैश्विक वस्त्र मेगा कार्यक्रम 11 वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों (TEPCs) के एक संघ द्वारा भारत की वस्त्र क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाएगा।
2024 में सरकार के गठन के पहले 100 दिनों की अवधि की प्रमुख पहलों में शामिल हैं	हथकरघा और हस्तशिल्प: कारीगरों और बुनकरों के कौशल विकास के लिए 'बुनकर और कारीगर उत्थान कार्यक्रम' की शुरुआत की गई; 10वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन किया गया। रेशम क्षेत्रक: गुजरात में एरी सिल्क परियोजना का शुभारंभ और केंद्रीय रेशम बोर्ड के प्लेटिनम जयंती समारोह का आयोजन। जूट क्षेत्रक: श्रमिकों और किसानों को लाभ पहुंचाने, आधुनिकीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए जूट की बोरियों के लिए एक नई मूल्य निर्धारण पद्धति। तकनीकी वस्त्र: तकनीकी वस्त्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, NTTM के तहत 11 स्टार्टअप का शुभारंभ और भारत की पहली AI-आधारित फैशन रुझान पूर्वानुमान प्रणाली विज़ननेक्सट (VisioNxt) की शुरुआत। अवसंरचना विकास: महाराष्ट्र में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक वस्त्र केंद्र के रूप में स्थापित करना है। वृहद आयोजन: अंतर्राष्ट्रीय निवेश और खरीदारों को आकर्षित करने के लिए एक वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम, भारत टेक्स 2025, का पूर्वावलोकन।

25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (Ministry of Earth Sciences: MoES)

पृथ्वी योजना	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की पृथ्वी योजना को 2021-26 की अवधि के लिए 4,797 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मंजूरी दी। इसमें ACROSS (वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान), O-SMART (समुद्री सेवाएं), और PACER (ध्रुवीय विज्ञान) जैसी महत्वपूर्ण उप-योजनाएं शामिल हैं।
मिशन मौसम	इसे 2,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू किया गया, यह पहल मौसम, जलवायु और महासागर विज्ञान में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	भारत ने जैव विविधता राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे (BBNJ) समझौते पर हस्ताक्षर किए, इसने समुद्री संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अपने EEZ (अनन्य आर्थिक क्षेत्र) से बाहर अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है।
तकनीकी प्रगति	- उन्नत निम्न-तापमान तापीय विलवणीकरण (LTTD) संयंत्रों के उद्घाटन और सुपर कंप्यूटर (अर्का और अरुणिका) के लॉन्च ने भारत के मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को बढ़ावा दिया। मुंबई में भारत का पहला शहरी रडार नेटवर्क लॉन्च किया गया, जिससे महानगरीय क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान को बढ़ावा मिला है।
गहरे समुद्र और आर्कटिक अनुसंधान	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिंद महासागर में एक सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की खोज को सुगम बनाया और कनाडाई पर्माफ्रॉस्ट से कोर नमूने प्राप्त करने सहित आर्कटिक अनुसंधान पहलों का समर्थन किया।
अवसंरचना विकास	देश भर में डॉप्लर मौसम रडार, मौसम अवलोकन प्रणाली और समुद्र विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठानों सहित कई उच्च तकनीक सुविधाओं का उद्घाटन किया गया।
वैज्ञानिक योगदान	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने "आपदाजनक मौसमी घटनाएं 2023" पर मेट मोनोग्राफ जैसी विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्ट्स जारी कीं, और तटीय स्वच्छता के लिए "स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर" अभियान जैसी प्रमुख पहलें शुरू कीं।

CSAT

क्रैश कोर्स प्रीलिम्स 2025

(इसका उद्देश्य मूलभूत अवधारणाओं को रिवाइज करना और उन्हें सुदृढ़ करना, समस्या-समाधान क्षमताओं को बढ़ाना, विश्लेषणात्मक कौशल को बेहतर बनाना, समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना और प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए समझ कौशल में सुधार करना है।)

प्रारंभ

English Medium
21 January, 1 PM

हिन्दी माध्यम
30 January, 1 PM

(Offline/Online)

26. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)	- PMUY के तहत 10.33 करोड़ गैस कनेक्शन जारी किए गए। - सभी उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपये/ सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी दी जा रही है।
LPG कवरेज	- PAHAL (प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ) योजना: PAHAL योजना के तहत 30.43 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता पंजीकृत हैं। 'गिव इट अप' अभियान: इसके तहत 1.14 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ दी है। 90 प्रतिशत से अधिक नए वितरक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रहे हैं।
एकीकृत पाइपलाइन टैरिफ	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने "एक राष्ट्र, एक ग्रिड और एक टैरिफ" के मिशन के साथ प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एकीकृत टैरिफ से संबंधित नियमों को शामिल करने के लिए PNGRB (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ का निर्धारण) विनियमों में संशोधन किया है।
किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (SATAT) पहल	2018 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य संपीड़ित बायो गैस (CBG) के उत्पादन और उपयोग के लिए उचित पारितंत्र विकसित करना है। - शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क में CBG के वितरण के लिए पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) के विकास हेतु एक योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य CBG संयंत्र से शहरी गैस वितरण ग्रिड तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
CGD संस्थाओं के लिए घरेलू गैस आवंटन की समीक्षा	CGD क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने और आम लोगों को मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए, सरकार ने नए CGD क्षेत्र गैस आवंटन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
घरेलू गैस मूल्य निर्धारण	- ONGC/ OIL के नामांकित क्षेत्रों, नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (NELP) ब्लॉक्स और पूर्व-NELP ब्लॉक्स से उत्पादित गैस के लिए अप्रैल 2023 में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जहां उत्पादन साझेदारी अनुबंध (PSC) के तहत सरकार की मंजूरी आवश्यक होती है। - ऐसी प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय क्रूड बास्केट के मासिक औसत का 10% होगी और इसे मासिक आधार पर अधिसूचित किया जाएगा और इसकी एक न्यूनतम और एक अधिकतम सीमा होगी।
बायो ईंधन और इथेनॉल मिश्रण	- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में औसतन 16.23% एथनॉल मिश्रित किया गया है। - ग्रीन हाइड्रोजन: तेल और गैस से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2030 तक 900 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं (EPC और BOO मोड) की योजना बनाई है। - सरकार ने 2027, 2028 और 2030 से क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) में SAF के 1%, 2% और 5% मिश्रण का लक्षित मानक निर्धारित किया है। - PM JI-VAN योजना को "2G इथेनॉल" के स्थान पर उन्नत बायो ईंधन को शामिल करके संशोधित किया गया है।
शोधन क्षमता	देश में 256.8 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की कुल शोधन क्षमता वाली 22 परिचालन रिफाइनरियां हैं।
अन्वेषण और उत्पादन	- हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (HELP): भारतीय तलछट बेसिनों में तेल और गैस के विशाल भंडार का दोहन करने के लिए, सरकार ने मार्च 2016 में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (HELP) के एक भाग के रूप में ओपन एक्जरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम (OALP) शुरू किया। - खोजे गए छोटे क्षेत्र के लिए नीति (DSF): सरकार ने वर्ष 2015 में DSF नीति शुरू की थी। - भारत में CBM: CBM ने ~6.38 BCM का संचयी उत्पादन हासिल किया है। - E&P के लिए खोले गए नो-गो क्षेत्र: अतन्त्र आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के लगभग 99% पूर्व 'नो-गो' क्षेत्र जो दशकों से अन्वेषण के लिए प्रतिबंधित थे, अब E&P के लिए खोल दिए गए हैं। - राष्ट्रीय डेटा रिपॉजिटरी: 2017 में लॉन्च की गई, यह सुविधा और अवसंरचना डेटा के संरक्षण, रखरखाव और प्रसार के लिए बनाई गई है, जिससे भविष्य के अन्वेषण और विकास के लिए इसका व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित हो सके। - राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम: 2016 में तैयार किया गया, यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों का मूल्यांकन करने के लिए है जहाँ के लिए शून्य या बहुत कम डेटा उपलब्ध था।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	- तेल और गैस स्रोतों का विविधीकरण: गैस-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने और विविधीकरण के लिए, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों IOCL और GAIL ने ADNOC, UAE के साथ दीर्घकालिक LNG आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वार्षिक रूप से लगभग 2.7 MMT LNG की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। - वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन: इसे भारत में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2023 में लॉन्च किया गया था, - इस गठबंधन में 28 सदस्य देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हो गए हैं और इसका विस्तार जारी है। - GBA सचिवालय भारत में स्थापित किया जाएगा। - पड़ोसी देशों के साथ सहयोग: भारत ने नेपाल और भूटान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। - स्वच्छ ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी: - भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 के अनुरूप रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी (SCEP) के जरिए अपनी साझेदारी को बढ़ाना जारी रखा है। - भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और टिकाऊ बायो ईंधन में सहयोग के लिए इटली के साथ एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए।
सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR)	- SPR चरण-I: मंगलौर; पादुर; विशाखापत्तनम में भंडार। - SPR चरण- II: PPP मोड पर चंदीखोल, पादुर में भंडार। - भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL): ओडिशा के जाजपुर जिले के चंदीखोल में परियोजना स्थल के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट और भू-तकनीकी सर्वेक्षण पूरा किया गया है। - परियोजना के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर द्वारा किया गया है।
हाइड्रोकार्बन परियोजनाएं और निवेश	- इन परियोजनाओं में रिफाइनरी परियोजनाएं, जैव रिफाइनरी, E&P परियोजनाएं, विपणन अवसंरचना परियोजनाएं, पाइपलाइन, CGD परियोजनाएं, ड्रिलिंग/ सर्वेक्षण गतिविधियाँ आदि शामिल हैं। - ऊर्जा निर्भरता को कम करना: नीतियों आदि के माध्यम से प्राकृतिक गैस के उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा, रिफाइनरी सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना।

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध


2025
**ENGLISH MEDIUM
25 JANUARY**
**हिन्दी माध्यम
25 जनवरी**
2026
**ENGLISH MEDIUM
25 JANUARY**
**हिन्दी माध्यम
25 जनवरी**

27. नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)

भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024	- इसे भारत के विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए पारित किया गया है। - यह विमान अधिनियम, 1934 को प्रतिस्थापित करता है। - यह स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देता है, और व्यापार सुगमता को बढ़ाता है।
उपलब्धियां	2024 में रिकॉर्ड यात्री यातायात: भारत में घरेलू यात्री यातायात में 5.9% की वृद्धि देखी गई, जो 146.4 मिलियन तक पहुंच गई। - सरकार ने पूरे भारत में 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। RCS-उड़ान योजना ने अपनी 8वीं वर्षगांठ मनाई, 619 मार्गों और 88 हवाई अड्डों का संचालन किया, जिसमें उत्तर-पूर्वी राज्यों में 20 सहित 2024 में 102 नए मार्ग शुरू किए गए। - भारत के 80 हवाई अड्डों ने 100% ग्रीन ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिया है, और बेंगलुरु हवाई अड्डे ने उच्चतम कार्बन प्रत्यायन स्तर हासिल किया है।
नई पहलें/बदलाव/घोषणाएं	उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन: इसका उद्घाटन कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को किफायती भोजन प्रदान करने के लिए किया गया था। सीप्लेन संचालन के लिए दिशा-निर्देश: सुरक्षा और दक्षता को प्राथमिकता देते हुए सीप्लेन संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। - सरकार ने पूरे भारत में 50 से अधिक जलाशयों में सीप्लेन संचालन के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की हैं। विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना: "नागरिक विमानन क्षेत्र में लैंगिक समानता" पर एक सलाह जारी की गई है, ताकि भारत के विमानन उद्योग में 2025 तक विभिन्न पदों पर महिलाओं की भागीदारी 25% तक बढ़ाई जा सके।

VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

विषयक रिवीजन क्लासेस

GS प्रीलिम्स

UPSC CSE 2025

11 फरवरी, दोपहर 1 बजे

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

Copyright © by **Vision IAS**

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of **Vision IAS**.

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates



Aditya Srivastava

79

in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**



Animesh Pradhan



Ruhani



Srishti Dabas



Anmol Rathore



Nausheen



Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =



मोहन लाल



अर्पित कुमार



विपिन दुबे



मनीषा धार्वे

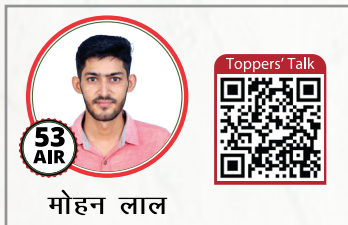


मयंक दुबे

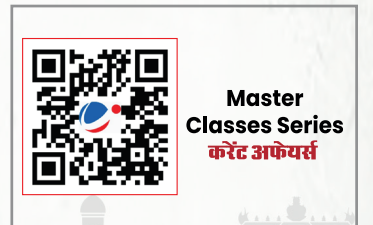
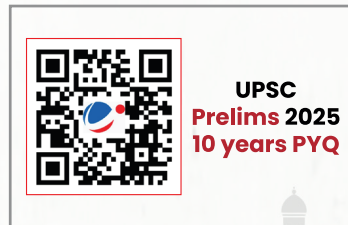


देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें



मोहन लाल



DELHI

HEAD OFFICE

Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor,
Near Gate-6 Karol Bagh
Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,
above Gate No. 2, GTB Nagar
Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066



enquiry@visionias.in



[@visioniashindi](https://www.youtube.com/@visioniashindi)



[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)



[/vision_ias_hindi/](https://www.instagram.com/vision_ias_hindi/)



[/hindi_visionias](https://www.telegram.com/hindi_visionias)

